

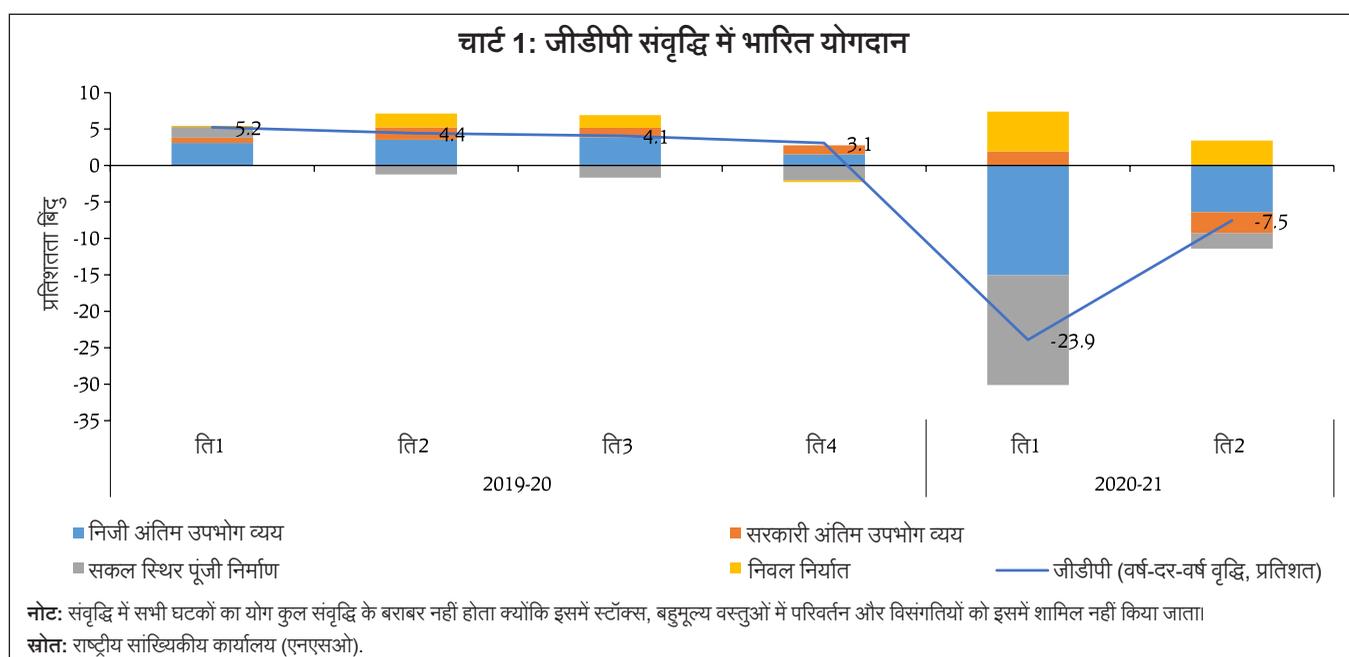
अर्थव्यवस्था की स्थिति*

पिछले माह के आलेख में प्रस्तुत आकलन के बाद से ऐसे और भी साक्ष्य मिले हैं जो यह दर्शाते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड-19 की निराशा से बाहर निकल रही है और तमाम पूर्वानुमानों को झुठलाने वाली गति से वापसी कर रही है। हालाँकि, मुश्किलें अभी भी हैं, परंतु यदि सभी हितधारक निरंतर दृढ़तापूर्वक अपने प्रयास जारी रखेंगे तो भारत और अधिक गति से विकास पथ पर बढ़ सकेगा।

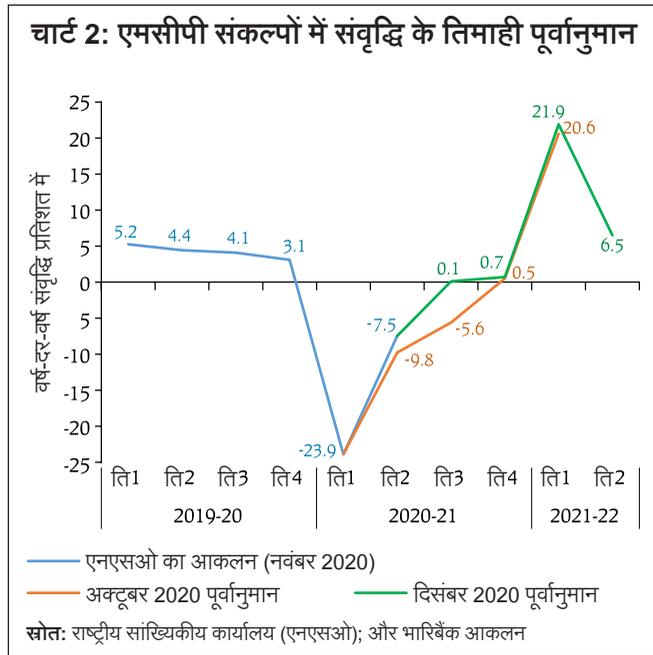
बीते माह के दौरान, ऐसे और भी सबूत मिले हैं जो यह दर्शाते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड-19 की घनघोर निराशा से बाहर निकल रही है और सर्दियों की लंबी घनी छाया के बीच से रास्ता बनाती हुई रोशनी की दुनिया में अपना आशियाना बना रही है। पहला सुखद आश्चर्य तब हुआ जब राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ) ने अपने नवंबर अंत के आंकड़े जारी किए – वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में महामारी द्वारा अर्थव्यवस्था को दिए गए घाव दूसरी तिमाही में तुलनात्मक रूप से काफी सतही साबित हुए और अर्थव्यवस्था की बहाली की दर इतनी अच्छी रही

है कि यह तमाम पूर्वानुमानों को पीछे छोड़ चुकी है (चार्ट 1)। दूसरा, पिछले महीने के बुलेटिन (कुमार, 2020) में प्रस्तुत किए गए तात्कालिक पूर्वानुमानों में अद्यतन आर्थिक गतिविधि सूचकांक (ईएआई) से यह संकेत मिलता है कि तीसरी तिमाही में वास्तविक जीडीपी वृद्धि के फिर से धनात्मक क्षेत्र में प्रवेश करने की उम्मीद है – हालांकि मात्र 0.1 प्रतिशत तक। तीसरा, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के चौथे द्विमासिक संकल्प में नीतिगत दरों को और रुख को तो यथावत बनाए रखा गया; लेकिन सख्त संदेश दिया गया: विकास के पूर्वानुमानों- लक्षित मुद्रास्फीति वाले एक लचीले फ्रेमवर्क के तहत मध्यवर्ती लक्ष्य और सबसे असरदार संचरण उपाय – में अक्टूबर की तुलना में 200 आधार अंकों का धनात्मक संशोधन किया गया और यदि यह प्रभावी रहा, तो भारतीय अर्थव्यवस्था 2020-21 की दूसरी छमाही के 0.4 प्रतिशत से आगे बढ़ते हुए 2021-22 की पहली छमाही में 14.2 की वृद्धि दर हासिल कर लेगी (चार्ट 2)।

वायरस से उत्पन्न परिस्थितियों में जो बदलाव आ रहा है, उसके पीछे दो महत्वपूर्ण ताकतें मिलकर काम करती नज़र आ रही हैं। प्रथम, भारत में कोविड-19 संक्रमण का वक्र झुकने लगा



* यह लेख आशीष थॉमस जॉर्ज, कृष्ण मोहन कुशवाहा, मधुरेश कुमार, कुणाल प्रियदर्शी, पलक गोदरा, जितेंद्र सोकल, मनु शर्मा, भानु प्रताप, शोभित गोयल, बरखा गुप्ता, साक्षी सूद, प्रियंका सचदेवा, ऋषभ कुमार, ऋषभ कुमार, रिज्जेन यांगडोल, राजस सरॉय, शशिधर एम. लोकरे और माइकल देवव्रत पात्र ने तैयार किया है। इस लेख में व्यक्त विचार इन लेखकों के निजी विचार हैं और जरूरी नहीं कि वे भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हों।



है: सितंबर मध्य के बाद से, कुछेक जगहों पर हुई वृद्धि को छोड़ दें, तो सप्ताह-दर-सप्ताह संक्रमण कम हो रहा है, और स्वस्थ होने की दर 95 प्रतिशत के स्तर को छू रही है। कई वैक्सीन न केवल परीक्षण की स्थिति में पहुंच गयी हैं, बल्कि उनके भारत में यातायात/परीक्षण/उपयोग संबंधी उपयुक्तता की जाँच भी की जा रही है (सारणी 1)। दूसरा, अब यह स्पष्ट हो रहा है कि राजकोषीय प्रोत्साहन एक तरीका होता है, एक 'पद्धति', यदि आप चाहें। चलनिधि / गारंटी के साथ प्रारंभ करते हुए अर्थव्यवस्था के लिए नकद / वस्तुओं के रूप में समर्थन – जो कि उस समय की

आवश्यकता थी जब महामारी ने करोड़ों लोगों से उनका जीवन और उनकी आजीविका छीन ली – यह अब धीरे-धीरे निवेश और उपभोग की मांग में वृद्धि में योगदान कर रही है। राजकोषीय उपायों को प्रधान मंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) में खपत व्यय से लेकर आत्म निर्भर 2.0 और 3.0 (चार्ट 3) में निवेश व्यय तक केंद्रित किया गया है। कुल मिलाकर, ऊपर-नीचे की राजकोषीय उत्तेजना 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद के 2 प्रतिशत के करीब बढ़ने की संभावना होगी (सरकारी वित्त पर बाद के लेख में बॉक्स 1 देखें)। दूसरे शब्दों में, उच्च आवृत्ति संकेतकों में निहित अस्थिरता से परे देखना समझदारी है। कंपनियां पहले से ही ऐसा कर रही हैं - 12 महीने के आगे की कमाई के विश्लेषण से बड़ी संख्या में कंपनियों के लिए दृष्टिकोण में सुधार का पता चलता है (चार्ट 4)। लॉकडाउन से बहुत अधिक प्रभावित ऑटो और कैपिटल गुड्स जैसे क्षेत्रों में भविष्य में कमायी में फिर से बेहतरी की उम्मीद की जाने लगी थी। हेल्थकेयर, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और अतिशय बिक्री वाली उपभोक्ता वस्तुओं (एफएमसीजी) की उत्पादक कंपनियां और अधिक आय की उम्मीद लगाए हुए हैं। इसके अलावा, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों को भीतर से मजबूत किया जा रहा है क्योंकि ऋण चुकौती क्षमता बेहतर हो रही है और कर्ज-पोषित आस्तियों की मात्रा को कम किया जा रहा है। विपणन के क्षेत्र में किए जा रहे नवोन्मेषी सुधार भारत के कृषि क्षेत्र को भी आगे ले जाने में सहयोगी बन रहे हैं। यह स्वीकार करना होगा कि भारत के समक्ष ऐसी अनेक बाधाएं अभी भी हैं जो बेहतर कल के

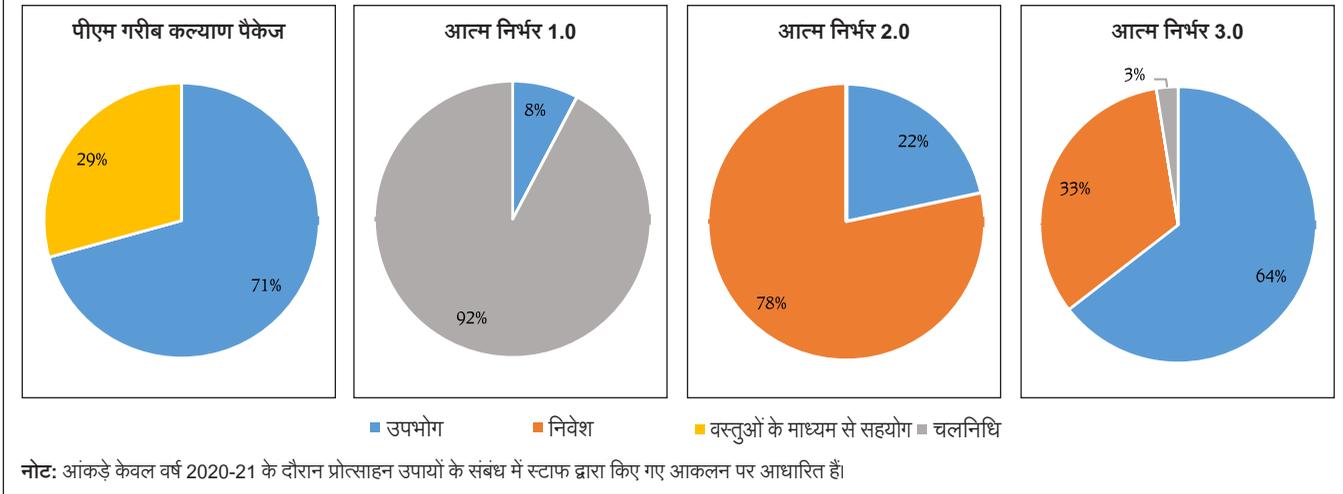
सारणी 1: कोविड-19 के टीके

कंपनी	प्रकार	खुराक	कितना प्रभावी	भंडारण
ऑक्सफोर्ड यूनी-एस्ट्राजेनेका	वायरल वेक्टर (आनुवंशिक रूप से संशोधित वायरस)	2	62-90%	सामान्य फ्रिज के तापमान पर
मॉडर्ना	आरएनए (वायरस आनुवंशिक कोड का हिस्सा)	2	95%	-20 डिग्री सेल्सियस, 6 महीने तक
फाइजर-बायोएनटेक	आरएनए	2	95%	-70 डिग्री सेल्सियस
गमलेया (स्पुतनिक वी)	वायरल वेक्टर	2	92%	सामान्य फ्रिज के तापमान पर
कैनसिनोबायो (ऐड5-एनकोव)	रिकॉम्बिनेंट एडेनोवायरस टाइप 5 वेक्टर			
सिनोफार्म: बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स	निष्क्रिय सार्स-कोव-2 (वेरो सेल)			
कोरोनावैक सिनोवैक	निष्क्रिय सार्स-कोव-2			
बीबीवी152 (कोवेक्सीन) भारत बायोटेक, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च	निष्क्रिय सार्स-कोव-2			
एनवीएक्स-कोव2373(145) नोवावैक्स	सार्स-कोव-2 रिकॉम्बिनेंट स्पाइक प्रोटीन नैनोपार्टिकल्स			

स्रोत: विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)

¹ रिकवरी दर कुल संक्रमित व्यक्तियों की तुलना में संक्रमण मुक्त हो चुके रोगियों की संख्या के रूप में पारिभाषित की जाती है।

चार्ट 3: प्रोत्साहन उपायों का असफल होना, सहयोग की प्रकृति के आधार पर

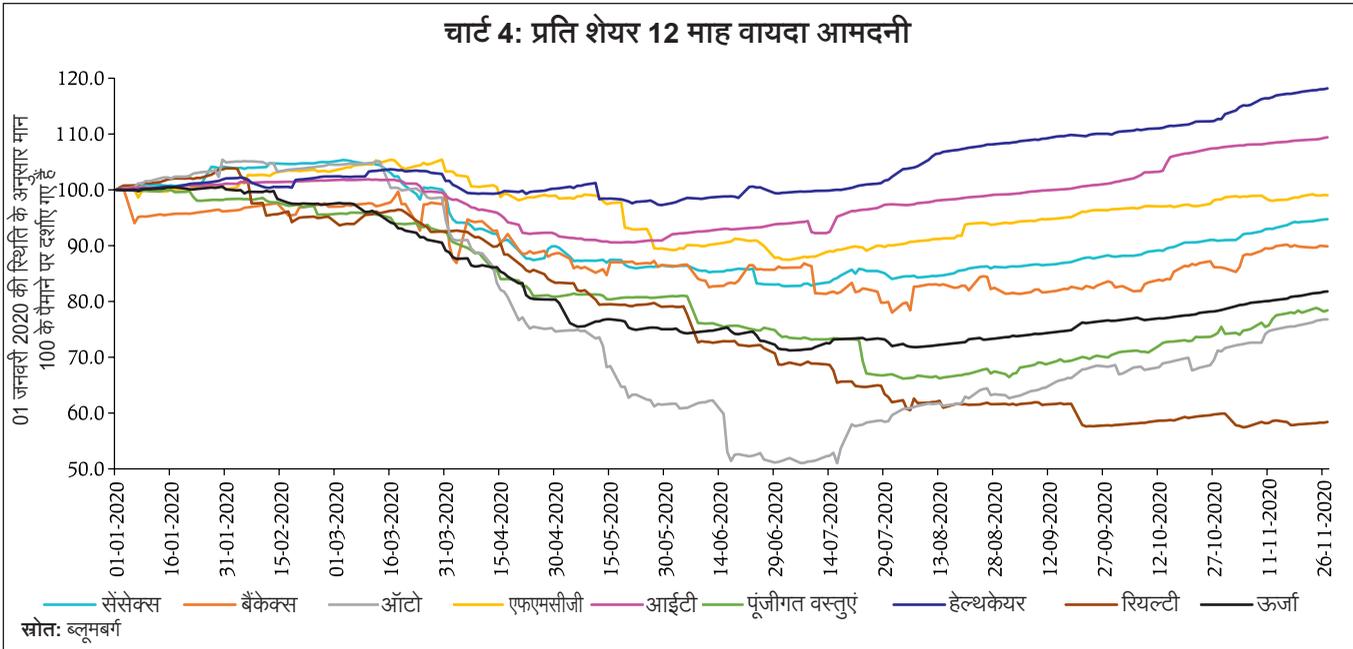


निर्माण के हमारे संकल्प में बाधक हैं, लेकिन अब हम उच्च आवृत्ति संकेतकों की ओर बढ़ रहे हैं और यह निश्चय ही एक आशा की किरण है। यह लेख पाँच खंडों में व्यवस्थित है। खंड II वर्तमान वैश्विक आर्थिक और वित्तीय बाजार की गतिविधियों का आकलन करता है। खंड III उच्च आवृत्ति संकेतकों में अंतर्निहित रुझानों का निचोड़ प्रस्तुत करता है। खंड IV में वित्तीय बाजार की बदलती स्थितियों की समीक्षा की गयी है, और अंतिम खंड निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं।

II. वैश्विक परिदृश्य

हालांकि वायरस के प्रकोप की दूसरी लहरों ने वैश्विक बहाली की दर पर रोक लगा दी, फिर भी यूएस में आए चुनाव परिणाम तथा काफी आगे के स्तरों तक पहुंच चुके क्लीनिकल परीक्षणों में 90 प्रतिशत से अधिक प्रभावी कोविड-19 वैक्सीन आ जाने की खबरों ने वैश्विक बाजारों में सरगमी ला दी। जोखिम लेने की क्षमता फिर से काफी बढ़ गयी दिखती है जिससे आस्तियों का प्रवाह जोखिम मुक्त निवेशों से बाहर आकर स्टॉक बाजार और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की ओर हो रहा है। यह विश्वास

चार्ट 4: प्रति शेयर 12 माह वायदा आमदनी



बढ़ता जा रहा है कि स्वास्थ्य से जुड़ी इस महामारी का अंत निकट है और आखिरकार वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए संभावनाएं साकार होती दिख रही हैं। परंतु साथ ही, दुनिया भर में व्यापक रूप से वैक्सीन पहुंचाने के लिए अपेक्षित तैयारियों से जुड़ी चुनौतियों के कारण वैक्सीन आ जाने की खबर से निकली आशा की किरण मद्धिम पड़ती नज़र आ रही है। 19 नवंबर को, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (अंकटाड) ने चेतावनी भरे स्वर में कहा – वैक्सीन के आ जाने के बाद भी अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसान पर विराम नहीं लगाया जा सकेगा और इसका प्रभाव भविष्य में लंबे समय तक महसूस किया जाएगा, विशेष रूप से सबसे गरीब और सबसे कमजोर तबके द्वारा, क्योंकि अत्यधिक गरीबी में गुजर बसर कर रहे लोगों की संख्या में 130 मिलियन लोग और जुड़ जाएंगे।

यह मानते हुए कि नए सिरों से बढ़ते वायरस के प्रकोप पर नियंत्रण कर लिया जाएगा, और 2021 के अंत तक वैक्सीन व्यापक रूप से उपलब्ध हो जाने की संभावना के मद्देनज़र उत्पन्न आत्मविश्वास के आधार आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) ने दिसंबर 2020 में व्यक्त अपने आर्थिक दृष्टिकोण में वर्ष 2020 के दौरान वैश्विक जीडीपी में 4.2 प्रतिशत की गिरावट और उसके बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था में धीरे-धीरे परंतु असमान बहाली दिखने और वैश्विक जीडीपी वर्ष 2021 में 4.2 प्रतिशत और वर्ष 2022 में 3.7 प्रतिशत की दर से वृद्धि होने का अनुमान व्यक्त किया गया है (सारणी 2)। 2021 के अंत तक, वैश्विक जीडीपी अपने महामारी-पूर्व के स्तर पर पहुंच जाएगी, लेकिन इसके प्रदर्शन में प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में स्पष्ट अंतर देखने को मिलेगा। भारत के बारे में, ओईसीडी की टिप्पणी है कि दुनिया के सबसे शुरुआती और सख्त लॉकडाउन के कारण वायरस के प्रसार को धीमा करने में मदद मिली। वर्ष 2020-21 में वास्तविक जीडीपी में 10 प्रतिशत की कमी आने और इसके बाद वापसी की उम्मीद है, लेकिन जीडीपी को महामारी-पूर्व का स्तर हासिल करने में लगभग दो साल लग सकते हैं। डिजिटल प्रौद्योगिकियों को उज्ज्वल पक्ष के रूप में देखा जा रहा है।

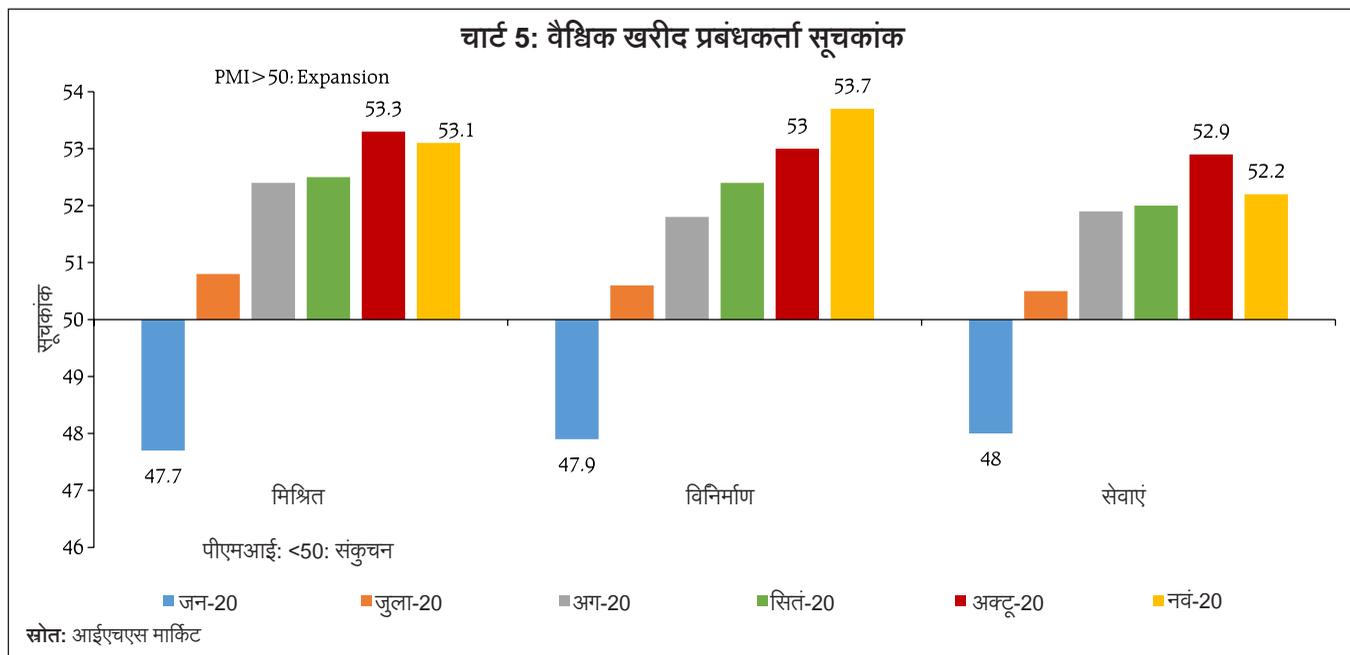
कुल मिलाकर, आर्थिक गतिविधियों में आए संकुचन के कारण वैश्विक आर्थिक परिदृश्य अभी भी अनिश्चित बना हुआ है। इन उलटफेरों को दर्शाते हुए, ग्लोबल कंपोजिट परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) नवंबर 2020 में घटकर 53.1 पर आ गया, जो एक महीने पहले (चार्ट 5) के दो साल के उच्चतम स्तर 53.3 पर था। नवंबर में लगातार पांचवें महीने विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन बढ़ा। वैश्विक सेवा क्षेत्र की व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी

सारणी 2: ओईसीडी आर्थिक परिदृश्य पूर्वानुमान दिसंबर 2020 – चुनिंदा आई और ईएमई

देश	2019	2020	2021	2022
 विश्व	2.7	-4.2	4.2	3.7
अग्रणी अर्थव्यवस्थाएं				
 यूएस	2.2	-3.7	3.2	3.5
 यूके	1.3	-11.2	4.2	4.1
 यूरो क्षेत्र	1.3	-7.5	3.6	3.3
 जापान	0.7	-5.3	2.3	1.5
उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं				
 चीन	6.1	1.8	8.0	4.9
 ब्राजील	1.1	-6.0	2.6	2.2
 रूस	1.3	-4.3	2.8	2.2
 दक्षिण अफ्रीका	0.2	-8.1	3.1	2.5
 भारत	4.2	-9.9	7.9	4.8

स्रोत: ओईसीडी आंकड़े

अक्टूबर की तुलना में थोड़ी मंद रही। उपभोक्ता सेवाओं में लगातार दसवें महीने सुस्ती आयी। संक्रमण की दूसरी लहर से उत्पन्न व्यवधानों और मांग पर पड़ी मार के कारण वैश्विक व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अंकटाड के अनुसार, वैश्विक व्यापार, जिसमें 2020 की दूसरी तिमाही में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 19 प्रतिशत की तीव्र गिरावट आयी थी, तीसरी तिमाही में भी संकुचन जारी रहा और लगभग 4.5 प्रतिशत की गिरावट आयी। इस गिरावट के दोगुना हो जाने की व्यापक आशंका के मद्देनज़र यदि आर्थिक गतिविधि और खराब नहीं हो जाती, तो चौथी तिमाही में संकुचन अपेक्षाकृत कम होगा और समान आधार पर गिरावट लगभग 3 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। सितंबर से ही घटती मांग की संभावनाओं के मद्देनज़र कच्चे तेल की टूटती कीमतें, 'वैक्सीन से जुड़ी आशाओं' के आधार पर तथा पेट्रोलियम उत्पादक देशों के संगठन (ओपेक) द्वारा उत्पादन में की गयी कटौती को आगे भी



जारी रखने के फैसले के कारण नवंबर माह में बढ़ने लगीं। नवंबर 2020 में उसकी औसत कीमत यूएस डालर \$43.23 प्रति बैरल रही जो कि एक माह पहले की उनकी कीमत से 6.8% अधिक थी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों से जुड़ी अनिश्चितताओं और संक्रमण में वृद्धि के कारण नवंबर की शुरुआत में सोने की कीमतों में थोड़ी तेजी आई। महीने के बाकी दिनों में, कीमतों में संशोधन हुआ और महीने भर में कुल मिलाकर 5.4 प्रतिशत की गिरावट आई जिसका कारण था वैक्सीन परीक्षण और अमेरिकी विनिर्माण क्षेत्र के आशावादी आंकड़े जिनकी वजह से अर्थव्यवस्था के प्रति सकारात्मक भावनाओं को गति मिली। पूरे वर्ष की तुलना में अद्यतन आधार पर अर्थात् दिसंबर 2019 के अंत तक स्वर्ण की कीमतों में 17.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

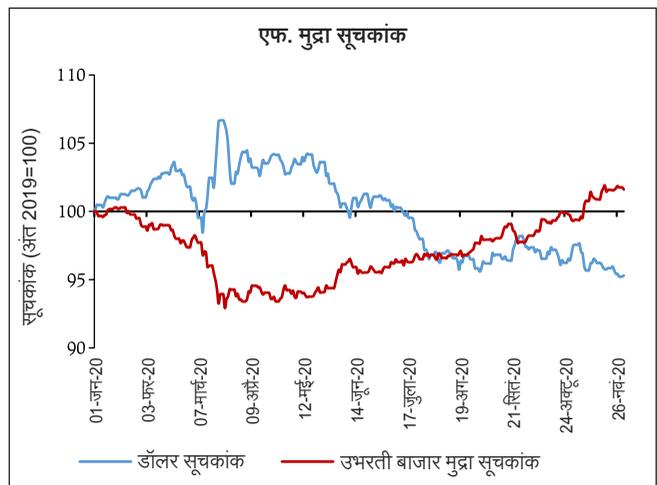
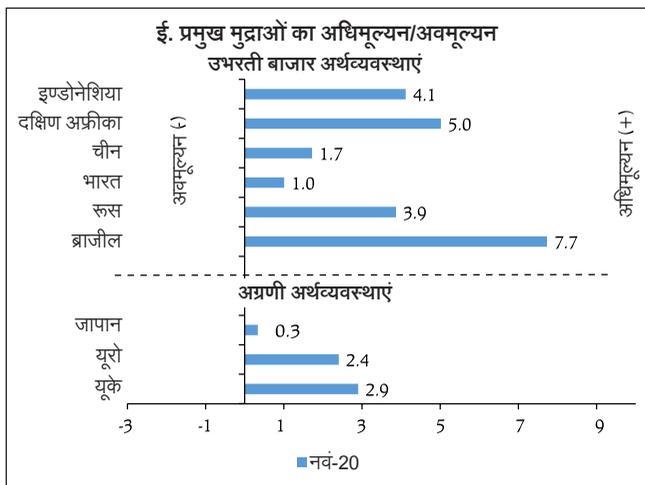
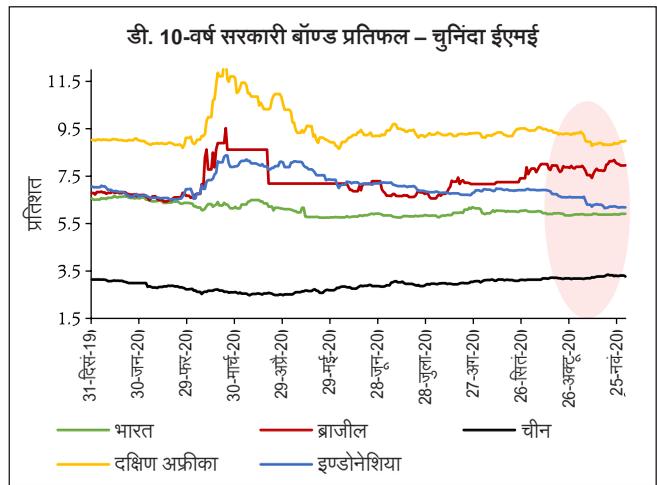
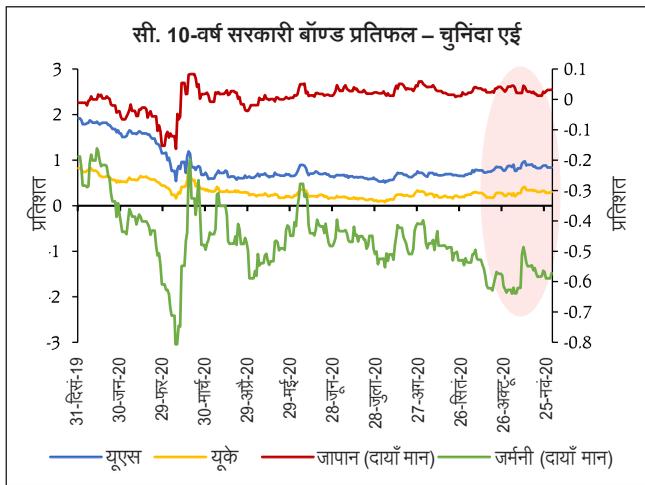
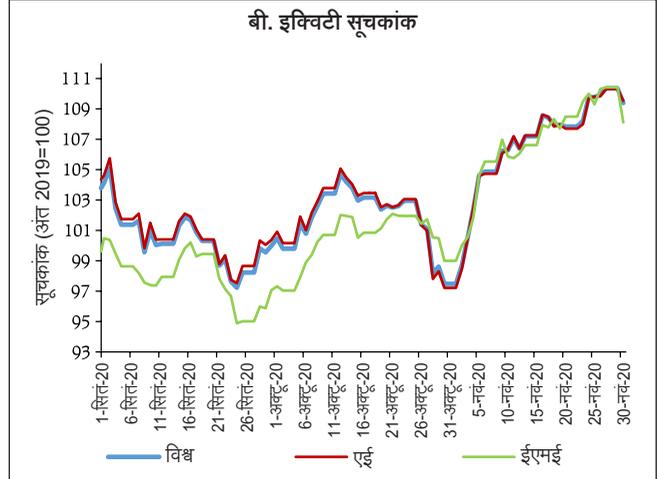
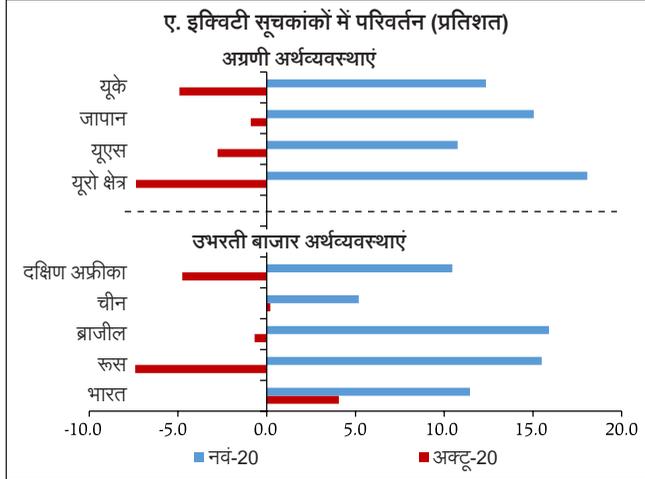
इक्विटी बाजार, जिनमें नवंबर की शुरुआत तक उतार-चढ़ाव जारी था- कभी थोड़े समय के लिए उछाल रहा तो कभी तेज बिकवाली दिखी वैक्सीन में हुई प्रगति के बल पर तीव्र उछाल देखने को मिला जिसने पिछले सभी रिकार्ड तोड़ दिए क्योंकि निवेशकों का विश्वास उन क्षेत्रों की ओर फिर से लौटने लगा था जिन पर महामारी की मार सबसे ज्यादा पड़ी थी और इस सबके ऊपर वह उत्साह तो था ही जो कारोबारी स्थितियों को बेहतर बनाये जाने के प्रयासों का नतीजा था (चार्ट 6)। मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया पूरे माह चलती रही और यह अंतर्निहित व्यापक आर्थिक स्थितियों तथा कॉर्पोरेट वित्त के हालात से बेमेल थी। कॉर्पोरेट बाजार के क्षेत्रों में क्रेडिट स्प्रेड और कम हुआ तथा थोड़ी बहुत

अस्थिरता के बीच महामारी-पूर्व के स्तर को छूने लगा। दूसरी ओर, बैंकों ने ऋण देने के मानकों को कड़ा कर दिया। केंद्रीय बैंक से प्राप्त हो रहा समर्थन जारी रहने के कारण, सरकारी बॉन्ड प्रतिफल असामान्य रूप से कम रहा, हालांकि दीर्घकालिक आधार पर अमेरिकी प्रतिफल में वृद्धि देखने को मिली। इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि, अधिकांश ईएमई में प्रतिफल कम रहा। अधिक प्रतिफल की तलाश जैसे-जैसे जोर पकड़ती गयी, ईएमई के प्रति नज़रिए में सुधार हुआ और इन अर्थव्यवस्थाओं में आने वाला पोर्टफोलियो निवेश बढ़ा। अमेरिकी डॉलर नवंबर में कमजोर हुआ, जिससे विशेष रूप से ईएमई मुद्राओं की कीमतें बढ़ीं, हालांकि इसमें कुछ अंतर देखा गया और तकनीकी रूप से अधिक सक्षम तथा वैश्विक मूल्य शृंखलाएं तैयार करने में ज्यादा शिद्धत के साथ जुटी ईएमई में यह वृद्धि अधिक रही। इसके विपरीत, कमोडिटी निर्यात पर अधिक निर्भर देशों की मुद्राओं में यह बदलाव सीमित रहा। कुल मिलाकर, नवंबर में अमेरिकी डॉलर 2.3 प्रतिशत कमजोर पड़ा, जिससे उसका संचयी ईयर-टु-डेड मूल्यहास 4.7 प्रतिशत हो गया। मॉर्गन स्टेनली कैपिटल इंटरनेशनल इमर्जिंग मार्केट्स (एमएससीआई-ईएम) इंडेक्स द्वारा प्रस्तुत ईएमई मुद्राओं की कीमतों में 1.6 प्रतिशत की ईयर-टु-डेड वृद्धि हुई जबकि अकेले नवंबर माह में ही यह वृद्धि 2.2 प्रतिशत रही। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस (आईआईएफ) के अनुसार, ईएमई में पोर्टफोलियो का प्रवाह नवंबर में 76.5 बिलियन डॉलर था, जिसमें इक्विटी और कर्ज की लगभग समान भागीदारी

(यूएस \$39.8 बिलियन और यूएस \$36.7 बिलियन, क्रमशः) थी। वर्ष 2013 की पहली तिमाही, अर्थात टेपर टैंट्रम से ठीक पहले,

के बाद से 2020 की चौथी तिमाही ही वह अवधि रही है जब ईएमई इनफ्लो सबसे अधिक रहा है।

चार्ट 6: वित्तीय बाजार घटनाक्रम

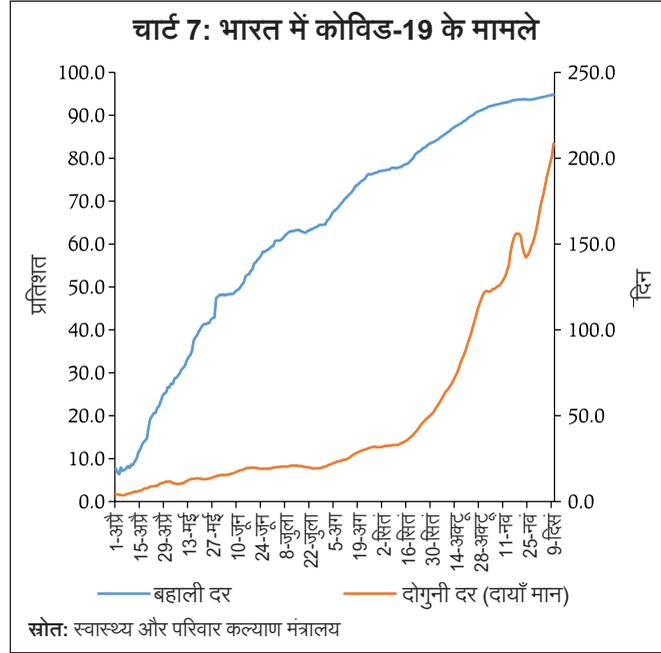


स्रोत: ब्लूमबर्ग

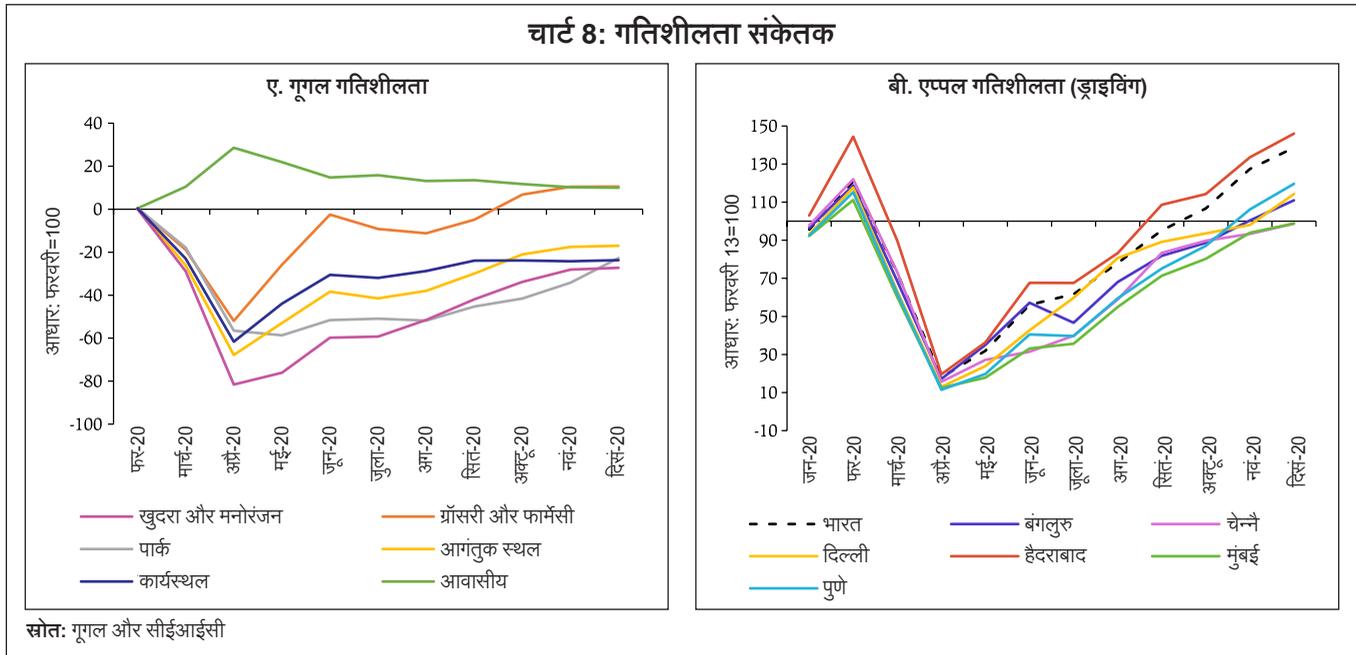
III. घरेलू क्षेत्र की गतिविधियाँ

भारत में विकास कई दृष्टियों से वैश्विक स्थितियों से भिन्न दिखायी पड़ता है। 10 दिसंबर, 2020 तक कुल संक्रमणों की संख्या 97,96,769 थी, जबकि कुल मौतों की संख्या 1,42,186 थी, लेकिन 92,90,834 व्यक्तियों का इलाज करके उन्हें ठीक किया गया। मामलों के दोगुना होने की दर² घटकर 208.6 दिन हो गई है जो कि 25 मार्च यानी लॉकडाउन लगाए जाने की तारीख को 3.5 दिन थी (चार्ट 7)। मृत्यु दर 1.5 प्रतिशत है, जो कि वैश्विक मृत्यु दर (2.2 प्रतिशत) की तुलना में काफी कम है। ठीक होने की दर में भी बहुत सुधार हुआ है जो लॉकडाउन की शुरुआत के 5% से बढ़कर 10 दिसंबर को 94.8% हो गयी है। इस लेख को प्रिंट करने के लिए दिए जाने के समय तक, सक्रिय मामलों की संख्या 4 लाख से भी कम हो गई थी और ऐसा जुलाई से लेकर अभी तक में पहली बार हुआ था। हालांकि अभी भी काफी खतरा बना हुआ है, फिर भी भारत अर्जेंटीना के अलावा एकमात्र ऐसा देश है, जिसे 'दूसरी लहर' का प्रकोप नहीं झेलना पड़ा है।

गतिशीलता का अपनी सामान्य स्थिति की ओर बढ़ना जारी है - गूगल मोबिलिटी इंडेक्स से संकेत मिलता है कि नवंबर में किराने के सामान और फार्मसियों के कारोबार में वृद्धि जारी रही है और इसने फरवरी में निर्धारित बेसलाइन स्तर को पार कर लिया है। आवासीय स्थानों से जुड़े कारोबार की गतिशीलता में



गिरावट जारी है, जबकि यह गतिशीलता कार्यस्थलों के मामले में स्थिर रही और मनोरंजन और खुदरा दुकानों के क्षेत्रों में अधिक हो गयी हालांकि महामारी पूर्व के बेसलाइन की तुलना में कम स्तर पर। इन संकेतों की पुष्टि ऐपल मोबिलिटी इंडेक्स द्वारा भी की गयी है, जिसने 13 जनवरी 2020 में तय अपने बेसलाइन स्तर को पीछे छोड़ दिया और इसमें मुख्य भूमिका पुणे, हैदराबाद और बेंगलूर शहरों ने निभाई। दिसंबर के अब तक (6 दिसंबर तक) के



² दोहराव दर को $\ln 2 / \ln (1 + r)$ के रूप में परिभाषित किया गया है, जहां r संचयी मामलों में पिछले सात दिनों में हुई वृद्धि का औसत है।

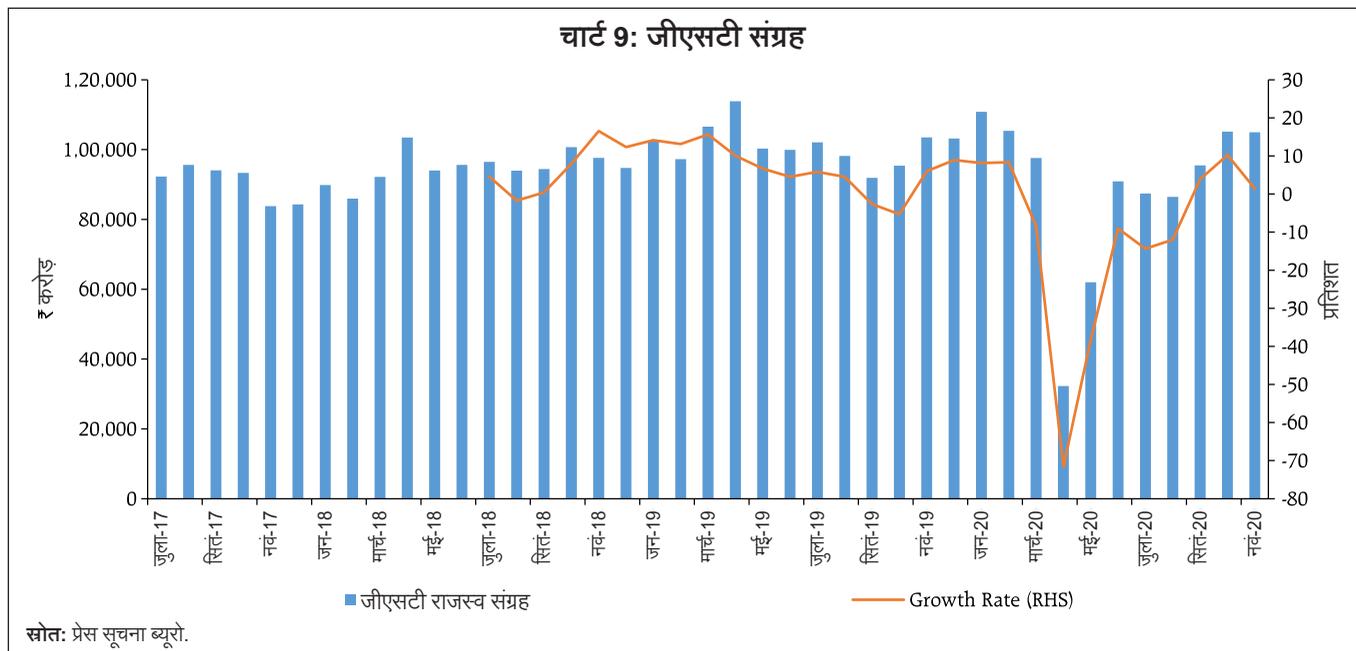
शुरुआती आंकड़े सभी शहरों में गतिशीलता सामान्य के आसपास आती दिखाते हैं (चार्ट 8)। नवंबर में सामानों की आवाजाही में भी तेजी आयी, जो कि ई-वे बिल जारी करने में हुई 8.1 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि से परिलक्षित होता है- अंतः-राज्यीय 9.6 प्रतिशत; और अंतर-राज्यीय 6.0 प्रतिशत - हालांकि पेंट-अप मांग कम हो जाने तथा त्योहारों से जुड़ा उत्पादन घटने के कारण कुछ मंदी देखी गयी।

कुल मांग

उच्च आवृत्ति संकेतक, जो तात्कालिक गतिविधियों को समझने के लिए कतिपय उतार-चढ़ाव प्रदर्शित करते हैं, उनका ग्राफ पिछले माह की तुलना में नवंबर माह में पठारी आकार का हो गया लेकिन कुल मिलाकर उन्होंने यही दर्शाया कि समग्र माँग में वृद्धि का रुख बना रहा। प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार, 2020-21 के दौरान नवंबर 2020 में बिजली की खपत लगातार तीसरे महीने वर्ष-दर-वर्ष आधार पर पिछले महीने के 11.1 प्रतिशत के अतिरिक्त 3.5 प्रतिशत और बढ़ी। पेट्रोल की खपत में जहाँ 5.0 प्रतिशत की तेजी आई, वहीं डीजल की खपत में संकुचन आना शुरू हो गया परंतु इसका कारण था - प्रतिकूल बेस प्रभावा अक्टूबर-मध्य से नवंबर-मध्य के बीच के त्यौहारी मौसम में, ई-विक्रेताओं – जिनमें फ्लिपकार्ट और अमेज़ॅन अग्रणी थे- का सकल कारोबार 65 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹58,000

करोड़ रहा। घरेलू खर्च को पूर्ववत बनाए रखते हुए, इस वित्त वर्ष में नवंबर माह में ऐसा दूसरी बार हुआ जब वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के तहत संग्रह ₹1 लाख करोड़ से अधिक रहा, जो वर्ष-दर-वर्ष 1.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है (चार्ट 9)। रिजर्व बैंक द्वारा करवाए गए उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (सीसीएस) के नवंबर 2020 चरण में उपभोक्ताओं की धारणा में सुधार दिखा जबकि पिछले चरण में यह अब तक के निम्नतम स्तर पर था। आर्थिक स्थिति, रोजगार की स्थिति, आय के परिदृश्य और व्यय-क्षमता में आम तौर पर सुधार आने की आशा से हाउसहोल्ड्स अब आगामी वर्ष को लेकर अधिक आश्वस्त हैं। इसकी पुष्टि रिफाइनिटिव-इम्प्रेस प्राइमरी कंज्यूमर सेंटीमेंट द्वारा भी की गयी है, जिसमें नवंबर 2020 के दौरान 2.6 प्रतिशत का तीव्र उछाल आया है जिसका कारण है रोजगार के प्रति विश्वास, आर्थिक प्रत्याशाओं, व्यक्तिगत वित्तीय स्थितियों और निवेश के माहौल में आया सुधारा

नवंबर के दौरान रोजगार की स्थितियों में भी सुधार हुआ। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) ने अपने हाउसहोल्ड्स सर्वेक्षण से बताया कि भारत की 40.03 प्रतिशत कामकाजी उम्र वाली आबादी ने श्रम बाजार में भागीदारी की, चाहे वह रोजगार करते हुए या रोजगार की तलाश में कार्य करते हुए। नतीजतन, बेरोजगारी की दर नवंबर 2020 में घटकर 6.51 हो गई, जो अक्टूबर 2020 में 6.98 थी, जो क्रमिक रूप से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आयी गिरावट थी। इस सकारात्मक

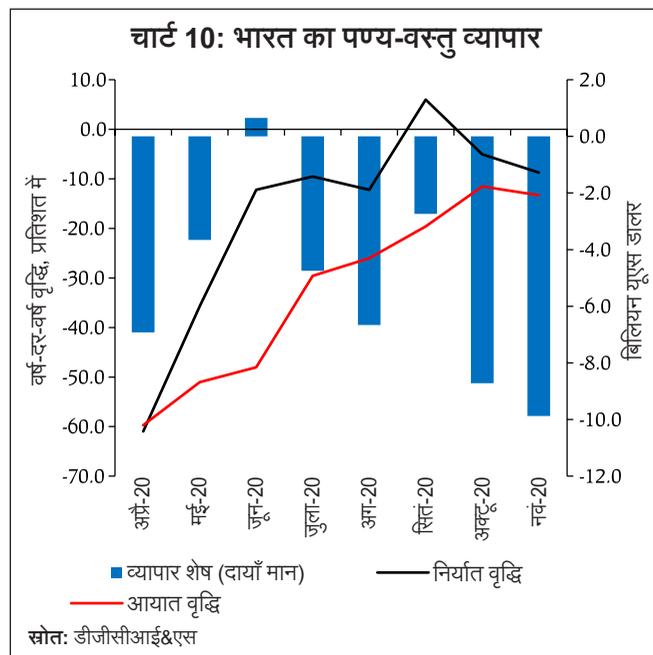


उतार-चढ़ाव को दर्शाते हुए, सेवाओं के लिए पीएमआई रोजगार सूचकांक नौ महीनों में पहली बार नवंबर 2020 में 50.4 पर पहुंचा (अक्टूबर 2020 में 46.8)। वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही के लिए जारी टीमलीज एम्प्लॉयमेंट आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार, किराए पर लेने के लिए समग्र इरादा रखने वालों में बड़े और मध्यम आकार के व्यवसाय अग्रणी बने रहे; हालांकि, जिन्होंने सबसे महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है, वे हैं छोटे आकार के व्यवसाय, यानी, लघु और मध्यम उद्यम (एसएमई)। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत, नवंबर 2020 में 25 प्रतिशत हाउसहोल्ड्स की रोजगार से जुड़ी मांग पूरी नहीं हो सकी जो इस बात का परिचायक है कि उनमें पुनः आजीविका प्राप्त करने की इच्छा है।

बाहरी मांग की ओर रुख करें तो, हालांकि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी अनंतिम आंकड़ों में नवंबर में कुल व्यापारिक निर्यात 23.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा जो वर्ष-दर-वर्ष 8.7 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है, तेल से इतर निर्यात ने लगातार तीसरे माह कोविड-19 पूर्व के स्तर को बनाए रखा (चार्ट 10)। दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स, कृषि, फार्मास्यूटिकल्स और लौह अयस्क जैसे क्षेत्रों में मजबूती दिखायी पड़ी। आयात में एक के बाद एक नौवें महीने गिरावट आई, हालांकि हाल के महीनों में इस संकुचन की गति कम हुई है। नवंबर 2020 में तेल आयात में 43.4 प्रतिशत की गिरावट आई है, लेकिन यह मूल रूप से कच्चे तेल की नरम पड़ी अंतरराष्ट्रीय कीमतों से प्रेरित है। दूसरी ओर, गैर-तेल आयात मोटे तौर पर कोविड-पूर्व स्तरों पर लौट आया है क्योंकि घरेलू मांग सामान्य होने लगी है। व्यापार घाटा नवंबर 2020 में बढ़कर 9.9 बिलियन यूएस डालर हो गया, जो चालू वित्त वर्ष का सर्वाधिक स्तर है। भविष्य की बात करें तो, प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) के तहत दस उभरते क्षेत्रों यथा- फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स / प्रौद्योगिकी उत्पादों, दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों और सौर कोशिकाओं-को भी शामिल कर लिया गया है जिसके परिणामस्वरूप ऐसी अपेक्षा की जानी चाहिए कि व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात में तेजी आएगी और वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत की भागीदारी बढ़ेगी।

सकल आपूर्ति

कृषि और विनिर्माण गतिविधि में तेजी आने के कारण नवंबर 2020 तक सकल आपूर्ति की स्थिति में सुधार जारी



रहा। सेवा क्षेत्र के भीतर भी, निर्माण क्षेत्र ने वापसी की, लेकिन संपर्क-केंद्रित सेवाएं कोविड-पूर्व स्तरों से कम और नीचे ही बनी रहीं।

महामारी के माहौल में भी कृषि क्षेत्र में मजबूती और तेजी बनी हुई है। इस साल 4 दिसंबर, 2020 तक 430.6 लाख हेक्टेयर या सामान्य बुआई क्षेत्र के 69.4 प्रतिशत भाग पर रबी की बुआई की जा चुकी है, जो एक साल पहले की इसी अवधि की तुलना में 3.9 प्रतिशत अधिक है (सारणी 3)। जलाशयों में पानी के पर्याप्त स्तर की मौजूदगी से बुआई में सहायता मिली है- 3 दिसंबर की स्थिति के अनुसार, जलाशयों का जल-स्तर अपनी पूरी क्षमता के 80 प्रतिशत के बराबर था, जबकि पिछले दशक में औसतन जल-स्तर 66 प्रतिशत रहा था। वर्ष-दर-वर्ष आधार पर देखें तो गेहूं की बुआई में लगभग 0.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, मुख्य रूप से मध्य प्रदेश (14.9 प्रतिशत) और पंजाब (3.2 प्रतिशत) में। इस वर्ष दलहन और तिलहन की बुआई में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इस बीच, खरीफ के चावल की खरीद एक साल पहले की तुलना में 22.1 प्रतिशत अधिक की गयी, जिसके कारण अनाज (चावल और गेहूं) का बफर स्टॉक 1 दिसंबर 2020 तक सामान्य से 2.4 गुना हो गया था।

औद्योगिक गतिविधियों की बात करें तो, विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) में नवंबर के दौरान वृद्धि जारी

सारणी 3: फसल की अखिल भारतीय स्थिति - रबी (2020-21), 4 दिसंबर 2020 की स्थिति

(लाख हेक्टेयर में)

फसल का नाम	सामान्य क्षेत्रफल		उक्त तारीख तक बुवाई की स्थिति		प्रतिशत भिन्नता	
	पूरे सीजन में	उक्त तारीख तक	इस वर्ष (2020)	विगत वर्ष (2019)	सामान्य की तुलना में	पिछले वर्ष की तुलना में
1. गेहूं	303.3	198.8	204.4	202.7	2.8	0.8
2. चावल	41.8	9.8	9.6	10.0	-2.6	-4.0
3. मोटे अनाज	57.1	41.2	33.0	35.6	-19.9	-7.2
ए. ज्वार	33.4	26.1	20.9	21.2	-19.7	-1.1
बी. जौ	6.4	5.7	4.9	5.8	-13.3	-14.8
सी. मक्का	17.4	8.9	6.6	8.1	-25.0	-18.0
4. कुल दलहन	144.9	114.3	116.6	103.0	2.0	13.2
ए. चना	92.8	78.3	82.2	70.7	5.0	16.2
बी. मसूर	14.2	13.1	13.1	12.1	-0.3	8.4
सी. मटर	8.8	7.5	8.2	7.2	10.2	14.7
डी. कुलथी (हॉर्स ग्राम)	2.2	3.7	3.1	3.9	-15.6	-19.5
ई. उड़द	8.9	3.8	3.4	3.5	-10.3	-3.0
एफ. मूंग	9.9	1.4	0.9	0.9	-38.6	-2.2
जी. खेसारी (लैथाइरस)	4.0	2.8	2.4	2.1	-15.5	11.4
आई. कुल खाद्यान्न (1+2+3+4)	547.1	364.1	363.5	351.3	-0.2	3.5
5. तिलहन	73.2	66.7	67.1	63.2	0.5	6.2
ए. राई और सरसों	59.4	59.5	61.8	57.4	3.9	7.7
बी. मूंगफली	7.3	2.6	2.1	2.3	-18.0	-8.1
सी. सूरजमुखी	2.4	1.2	0.6	0.6	-54.6	-9.9
डी. तिल	0.0	0.2	0.2	0.3	-19.6	-26.2
ई. कुसुम	1.2	0.6	0.4	0.3	-26.9	35.0
एफ. अलसी	2.7	2.3	1.8	2.1	-22.8	-12.4
सभी- फसलें (1+2+3+4+5)	620.3	430.8	430.6	414.4	-0.1	3.9

उक्त दिनांक को सामान्य क्षेत्रफल: 2014-15 से 2018-19 तक की इसी अवधि के दौरान औसत क्षेत्रफल।

सामान्य क्षेत्रफल: 2014-15 से 2018-19 तक की अवधि के दौरान औसत क्षेत्रफल।

नोट: क्षेत्रफल के आंकड़े राज्यों के कृषि विभागों द्वारा देखकर किए गए आकलन के अनुसार दिए गए हैं।

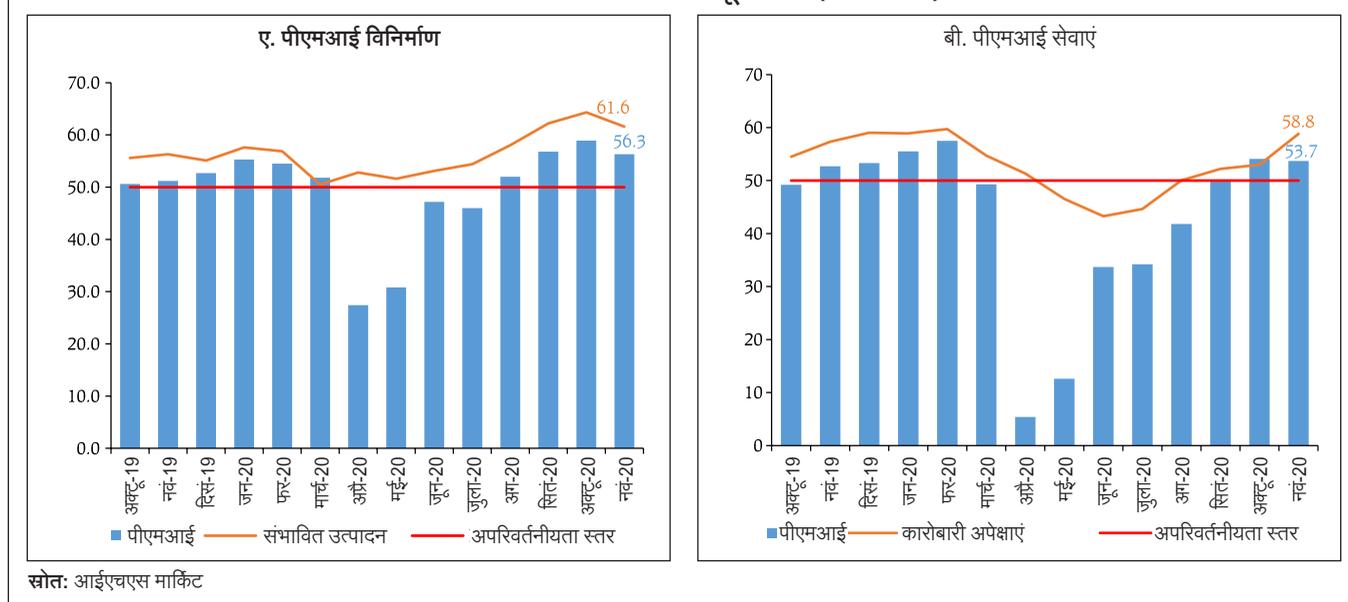
स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

रही, हालांकि पिछले माह यह अपने एक दशक के उच्चतम स्तर पर पहुंच कर नीचे फिसला और 56.3 पर आ गया (चार्ट 11)। अक्टूबर माह के लिए 12 दिसंबर को जारी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक ने इस ओर संकेत किया कि चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरे महीने औद्योगिक गतिविधियों की वृद्धि की रफ्तार अपने उच्चतम स्तर पर बनी रहेगी। रिजर्व बैंक के औद्योगिक परिदृश्य

सर्वेक्षण (आईओएस) के 91वें दौर पर फर्मों से प्राप्त प्रतिसाद में यह देखा गया कि वे इस बात को लेकर आशान्वित हैं कि 2020-21 की दूसरी तिमाही से फिर से जो तेजी दिखनी शुरू हुई थी, वह और जोर पकड़ेगी। इस आशा का आधार था- वित्त की उपलब्धता और साथ ही बाहरी मांग में सुधार एवं नौकरियों के मामले में जारी सुधारात्मक कार्रवाई।

सेवा क्षेत्र के भीतर, एक उल्लेखनीय सुधार चल रहा है, और कई संकेतक इसमें तेज वृद्धि दर्शाते हैं। घरेलू क्षेत्र में नये कार्यों के आने से सेवाओं का पीएमआई लगातार दूसरे महीने बढ़ते हुए नवंबर में 53.7 हो गया। विशेष रूप से निर्माण क्षेत्र में 2020-21 की तीसरी तिमाही में सुधार के स्पष्ट संकेत दिखे। निर्माण गतिविधि का एक महत्वपूर्ण संपाती सूचक - स्टील की खपत - में अक्टूबर में आए 2.6 प्रतिशत के संकुचन के बिलकुल विपरीत नवंबर में 11.0 प्रतिशत की तेजी आयी। इसी तर्ज पर चलते हुए, अक्टूबर 2020 में सीमेंट उत्पादन ने संकुचन के दौर से बाहर निकलते हुए 2.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की और नवंबर में इसमें और अधिक वृद्धि की उम्मीद है। जैसा कि ई-वे बिलों से संकेत मिलता है, नवंबर में व्यापार गतिविधि में वृद्धि का रुख रहा, लेकिन पिछले महीने में त्योहारों के कारण रहे उच्च स्तर की तुलना में ये गतिविधियाँ धीमी रहीं। यातायात सेवा क्षेत्र में अगस्त 2020 में वृद्धि का जो दौर शुरू हुआ था, उसे रेलवे माल ढुलाई में 9.0 प्रतिशत की वृद्धि के कारण समर्थन मिला। यात्री यातायात क्षेत्र अच्छा रहा और इसमें लॉकडाउन लगाए जाने के कारण आए संकुचन के बाद माह-दर-माह सुधार हुआ। निवेश सूचना और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (आईसीआरए) के अनुसार, घरेलू हवाई यात्रा की मांग फिर से बढ़ी क्योंकि यात्री यातायात में 19 प्रतिशत की क्रमिक वृद्धि हुई और यह नवंबर 2020 में 62.0 लाख हो गया। संपर्क से बचने के लिए लोगों द्वारा व्यक्तिगत वाहनों को तरजीह दिए जाने के साथ-ही-साथ लगातार चौथे महीने नवंबर में भी यात्री वाहन बिक्री में तेजी दर्ज की गई। यात्री कारों के अग्रणी निर्माताओं को छोड़कर, अन्य सभी मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) ने महीने के दौरान उच्च वृद्धि दर्ज की जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में बिक्री का महत्वपूर्ण योगदान रहा। नवंबर में हुआ वाहन पंजीकरण, हालांकि, अधिक सतर्क आशावाद को दर्शाता है।

चार्ट 11: खरीद प्रबंधकर्ता सूचकांक (पीएमआई)



मुद्रास्फीति

सीपीआई मुख्य मुद्रास्फीति एक महीने पहले 6.9 प्रतिशत से घटकर नवंबर में 7.6 प्रतिशत हो गयी, जो मुख्य रूप से क्रमिक आधार पर खाद्य स्फीति 1.3 प्रतिशत अंकों की गिरावट के कारण थी; हालाँकि, मुद्रास्फीति उच्च स्तर पर बनी रही और यह ऊपरी सहनीय सीमा के ऊपर रही। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामलों के विभाग) से प्राप्त

दिसंबर माह में अब तक (16 दिसंबर 2020 तक) के उच्च आवृत्ति खाद्य कीमत आंकड़े प्याज, आलू, टमाटर, अरहर, मसूर, चावल और गेहूं की कीमतें कुछ कम होने का संकेत देते हैं। खाद्य तेलों में मूल्य वृद्धि पूरे दिसंबर माह में निरंतर जारी रही है। कुल मिलाकर, डीसीए डेटा के आधार पर, आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतों में दिसंबर में 0.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि नवंबर में यह वृद्धि 2.0 प्रतिशत थी (तालिका 4)।

सारणी 4: डीसीए आवश्यक वस्तुओं की कीमतें

क्र. सं.	वस्तुएं	सीपीआई में भारिता	₹ प्रति कि.ग्रा.			माह-दर-माह (प्रतिशत)		
			दिसं-19	नवं.20	दिसं.20*	अक्टू.-20	नवं.-20	दिसं.20*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	अनाज (चावल + गेहूं)	6.9	31.8	32.9	32.7	-0.2	0.5	-0.8
	चावल	4.4	33.5	35.0	34.8	0.4	0.4	-0.7
	गेहूं और आटा	2.6	29.0	29.3	29.1	-1.2	0.5	-0.9
II	दलहन	2.0	83.0	97.4	97.1	5.8	1.9	-0.3
	तूर / अरहर दाल	0.8	88.4	106.6	105.6	10.2	2.0	-0.9
	उड़द दाल	0.3	96.4	106.4	107.3	5.0	2.4	0.8
III	खाद्य तेल	3.0	106.6	124.6	128.8	1.7	2.6	3.3
	सरसों का तेल	1.3	113.7	132.7	137.0	1.7	3.1	3.3
	रिफाईंड तेल	1.3	93.0	109.9	114.5	1.8	2.5	4.1
IV	सब्जियां (पीओटी)	2.2	46.6	48.0	42.7	12.9	8.6	-11.0
	आलू	1.0	25.4	44.6	41.7	7.7	12.8	-6.4
	प्याज	0.6	95.0	59.3	48.1	59.0	18.0	-18.9
	टमाटर	0.6	29.0	41.2	38.3	-12.4	-9.3	-7.0
V	सुगर	1.1	39.2	40.0	40.0	-0.4	-0.4	0.0
VI	दूध	6.4	44.9	47.1	47.3	0.1	0.4	0.5
VII	भारित औसत मूल्य	22.9	59.2	64.8	65.1	2.1	2.0	0.5

*: 1 दिसंबर से 16 दिसंबर 2020 के दौरान रही कीमतों के आधार पर।

नोट: भारित औसत मूल्य से अभिप्राय 22 आवश्यक खाद्य पदार्थों के औसत मूल्य से जिनकी भारिता सीपीआई बास्केट में उनकी हिस्सेदारी से निर्धारित होती है।

स्रोत: उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार तथा आरबीआई स्टाफ के अनुमान

पेट्रोलियम उत्पादों की श्रेणी में, उत्पाद शुल्क और राज्य करों ने पंप की कीमतों को ऊंचा बनाए रखा। नवंबर के दूसरे पखवाड़े में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के कारण 20 नवंबर 2020 से घरेलू पंप की कीमतों में तेजी आना शुरू हो गयी है। दिसंबर माह में अब तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में क्रमशः 2.4 फीसदी और 3.6 फीसदी बढ़ोतरी देखी गयी। एलपीजी की कीमतें जुलाई-नवंबर 2020 के दौरान स्थिर बने रहने के बाद दिसंबर में ₹100 प्रति सिलेंडर बढ़ गयीं, जिसने लोगों का चैन छीन लिया और पहले से दबावग्रस्त घरेलू बजट की स्थिति और भी बिगड़ गयी। बढ़ती अंतरराष्ट्रीय कीमतों के परिणामस्वरूप दिसंबर में केरोसीन की कीमतों में भी लगभग ₹1 प्रति लीटर और इजाफा हुआ (तालिका 5)।

वस्तुओं की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय कीमतों और घरेलू क्षेत्र द्वारा निर्मित वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों पर इसके बढ़ते प्रभाव के कारण ऐसी फर्में जो मार्जिन को बढ़ाते हुए और मांग के सामान्य स्थिति में आने के कारण मुख्य मुद्रास्फीति पर दबाव बढ़ रहा है। नवंबर के लिए विनिर्माण पीएमआई में, इनपुट कीमतों में और वृद्धि हुई है तथा जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था में गिरावट की दर कम होगी और मांग में वृद्धि आएगी, इसका असर निश्चित रूप से बिक्रय मूल्यों पर पड़ेगा। नतीजतन, उत्पाद-कीमतों में अब तक हो रही मामूली वृद्धि और मौजूदा कमजोर पड़ी हुई मूल्य निर्धारण शक्ति में कहीं अधिक इजाफा होगा। यह नवंबर की सीपीआई में भी देखा गया जहाँ खाद्य और ईंधन से इतर

मुद्रास्फीति नवंबर में भी 5.8 प्रतिशत के उच्च स्तर पर बनी रही जो अक्टूबर में 5.9 प्रतिशत थी।

IV. वित्तीय स्थितियाँ

चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत औसत दैनिक शुद्ध अवशोषण बढ़कर ₹5,63,589 करोड़ हो जाने के कारण नवंबर 2020 में प्रणालीगत चलनिधि का और अधिक विस्तार हुआ बावजूद इसके कि त्यौहारों के कारण बढ़ी हुई मुद्रा की मांग के चलते संचलनगत मुद्रा (सीआईसी) में अच्छी-खासी वृद्धि हुई थी। अधिशेष चलनिधि रात्रिपर्यंत रिवर्स रिपो के माध्यम से अवशोषित कर ली गयी थी और 30 नवंबर 2020 तक कुल मिलाकर ₹6,76,413 करोड़ का चलनिधि अवशोषण हुआ था। जैसा कि 9 अक्टूबर को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषित किया गया था, जिन बैंकों ने पहले लक्षित दीर्घावधि रिपो परिचालन (TLTRO और TLTRO 2.0) के तहत निधि प्राप्त की थी, उन्हें इस राशि को परिपक्वता से पहले लौटाने का विकल्प दिया गया। तदनुसार, बैंकों ने ₹37,348 करोड़ रुपये लौटाए। रिज़र्व बैंक ने 5 नवंबर 2020 को राज्य विकास ऋण (एसडीएल) में एकमुश्त खुले बाजार परिचालन (ओएमओ) के जरिये खरीद की और ₹10,000 करोड़ की टिकाऊ चलनिधि का अंतर्वेशन किया। प्रतिफल वक्र के सभी परिपक्वता स्पेक्ट्रम में चलनिधि वितरित करने के उद्देश्य से, रिज़र्व बैंक ने खुले बाजार परिचालन (विशेष ओएमओ) के तहत 12, 19 और 26 नवंबर, 2020 को प्रतिभूतियों की खरीद और

सारणी 5: पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें (चार बड़े महानगरों का औसत)

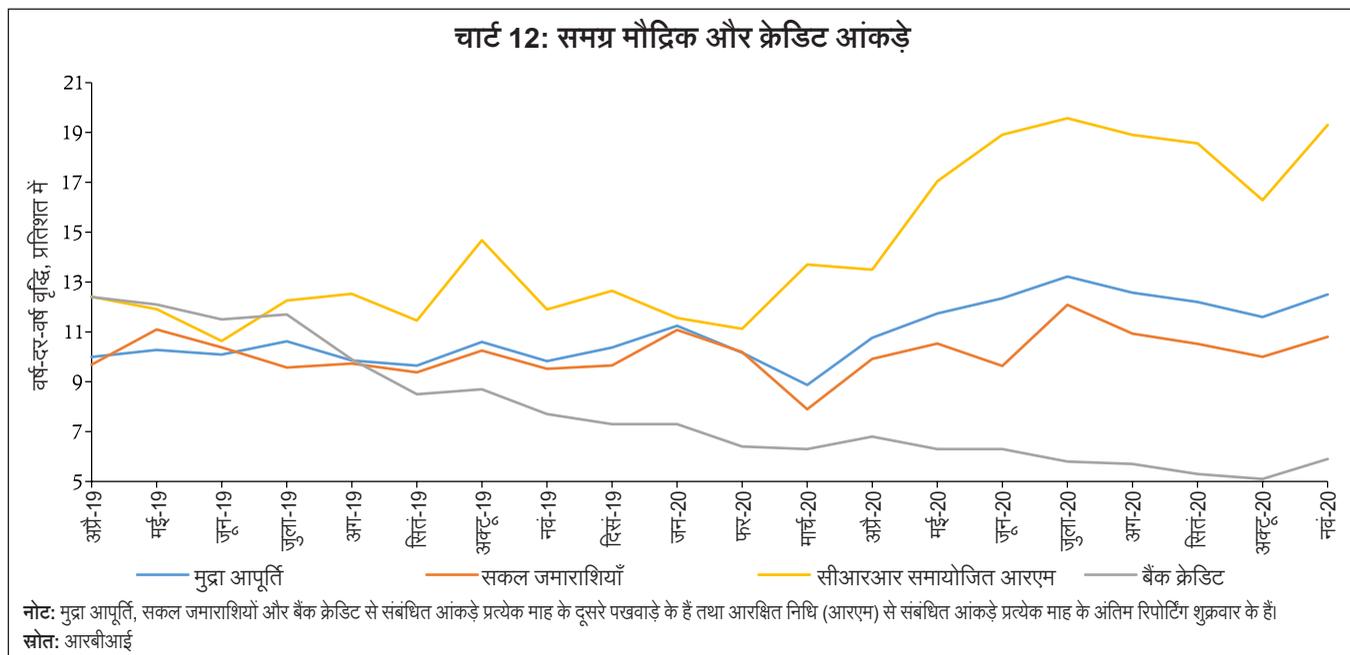
उत्पाद	इकाई	घरेलू कीमतें			माह-दर-माह (प्रतिशत)	
		दिसं.-19	नव.-20	दिसं.-20	नव.-20	दिसं.-20
पेट्रोल	₹/लीटर	77.64	84.13	86.12 ^	0.3	2.4
डीजल	₹/लीटर	68.77	74.73	77.43 ^	0.6	3.6
केरोसीन	₹/लीटर	28.80	22.17	23.21	3.3	4.7
एलपीजी	₹/लीटर	699.88	604.63	704.63*	0.0	16.5

^: 1-16 दिसंबर 2020 के दौरान मौजूद कीमतों पर आधारित।

*: दिसंबर, 2020 से लागू

नोट: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) द्वारा चार प्रमुख महानगरों (चेन्नई, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता) में प्रभारित कीमतों का औसत।

स्रोत: आईओसीएल, पेट्रोलियम आयोजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ, (पीपीएसी), भारत सरकार और भारिबैं स्टॉफ का अनुमान।



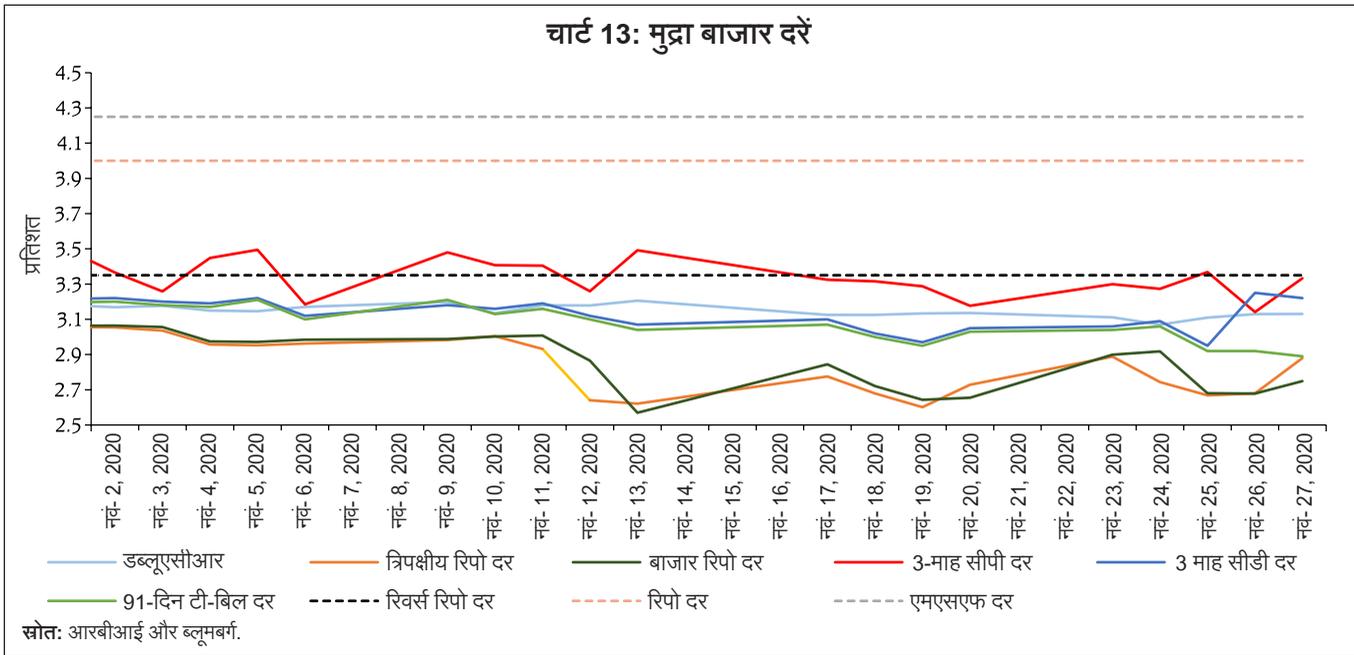
बिक्री के तीन परिचालन साथ-साथ किए जिनमें से प्रत्येक ₹10,000 करोड़ रुपये का था।

वर्ष 2020-21 के दौरान अब तक मौद्रिक और ऋण की स्थितियाँ सुगम हुई हैं और इससे आर्थिक गतिविधियों को पुनर्जीवन प्रदान करने में सहायता मिलेगी। 27 नवंबर 2020 की स्थिति के अनुसार, नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में प्रथम चरण के प्रभाव के लिए समायोजित रिजर्व मनी (आरएम) में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 19.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई (जो एक साल पहले 11.9 प्रतिशत थी)। 20 नवंबर 2020 को समाप्त पखवाड़े के लिए कुल जमा राशि में 10.8 प्रतिशत की वृद्धि होने के साथ, मुद्रा आपूर्ति (एम3) में 12.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई (जो एक साल पहले 9.8 प्रतिशत थी) [चार्ट 12]।

वाणिज्यिक क्षेत्र में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का क्रेडिट 20 नवंबर 2020 तक वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 5.8 प्रतिशत बढ़ा, जो कि पूर्ववर्ती महीने के अंतिम पखवाड़े में हुई 5.1 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि से अधिक था जिसका प्रमुख कारण था उत्साहजनक माहौल। टीएलटीआरओ का ही प्रभाव था कि वाणिज्यिक पत्र, बॉन्ड / डिबेंचर और कॉरपोरेट निकायों

के शेयरों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश में वर्ष 2020-21 (20 नवंबर तक) के दौरान ₹850 करोड़ की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में उनके इस निवेश में ₹24,611 करोड़ की गिरावट आयी थी।

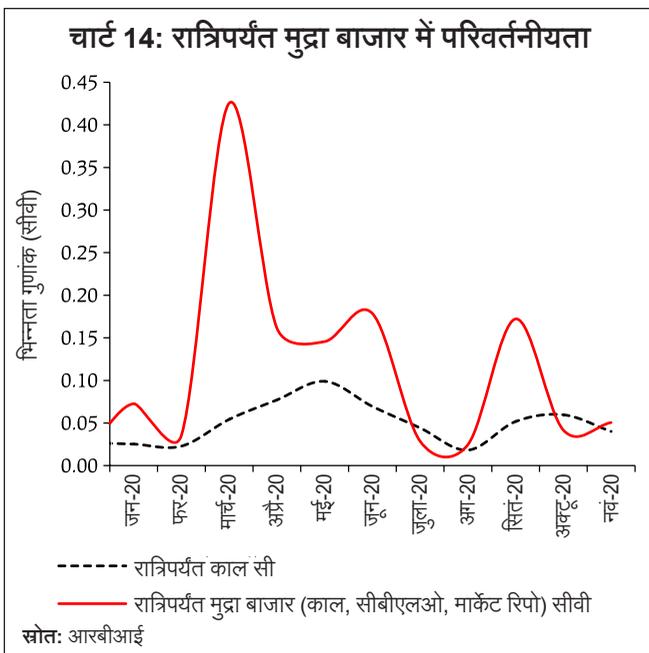
बैंकिंग प्रणाली में अधिशेष चलनिधि की स्थिति ने नवंबर में मुद्रा बाजार की दरों को और नीचे धकेल दिया है। रात्रिपर्यंत संपार्श्विक-मुक्त ऋण संविभाग में, भारत औसत कॉल दर डब्ल्यूएसीआर) अक्टूबर 2020 के अंतिम सप्ताह से रिवर्स रिपो दर से नीचे आ गई है। संपार्श्विक आधारित ऋण संविभाग में - मार्केट रिपो और त्रि-पक्षीय रिपो - दरें कॉल दर से क्रमशः 29 आधार अंक (बीपीएस) और 32 बीपीएस कम रहीं। निकट अवधि संविभाग, यानि जमा प्रमाण-पत्रों और 91-दिवसीय ट्रेजरी बिलों, में दरें रिवर्स रिपो दर से कम बनी रहीं। वाणिज्यिक पत्र पर बट्टाकरण की दर कई मौकों पर एलएएफ रिवर्स रिपो दर से नीचे आ गई और 26 नवंबर 2020 को घटकर 3.14 प्रतिशत के स्तर को छूने लगी (चार्ट 13)। रात्रिपर्यंत मनी मार्केट में मौजूद अस्थिरता, जो मार्च 2020 के महीने में चरम पर थी, पिछले कुछ महीनों में कम हुई है (चार्ट 14)।



अधिशेष चलनिधि के परिणामस्वरूप सभी वित्तीय बाजारों के प्रतिफल में वृद्धि हुई, विशेष रूप से मुद्रा और कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजारों में (सारणी 6)। 27 नवंबर, 2020 को 10-वर्षीय जी-सेक बेंचमार्क (5.77 जीएस 2030) का प्रतिफल 5.91 प्रतिशत पर पहुंच गया। 27 नवंबर 2020 को की गयी प्राथमिक बाजार नीलामी में नए 10-वर्षीय जी-सेक बेंचमार्क का कट ऑफ

प्रतिफल 5.85 प्रतिशत तय किया गया, जो 10-वर्षीय बेंचमार्क पर कारोबार के उस समय के मौजूदा प्रतिफल से कम था।

रिजर्व बैंक द्वारा किए गए चलनिधि संबंधी और अन्य उपायों के कारण वित्तीय स्थितियों में हुए निरंतर सुधार के चलते, कॉर्पोरेट बॉन्ड स्प्रेड लगभग सभी रेटिंग श्रेणियों में घटकर कोविड-पूर्व के स्तर पर पहुंच गया (सारणी 7)।



सारणी 6: वित्तीय बाजार - दरें और स्प्रेड

लिखत	ब्याज दरें (प्रतिशत)			स्प्रेड (बीपीएस) (संगत जोखिम-मुक्त दरों के ऊपर)		
	29 अक्टू 2020 की स्थिति	27 नव 2020 की स्थिति	भिन्नता (बीपीएस में)	29 अक्टू 2020 की स्थिति	27 नव 2020 की स्थिति	भिन्नता (बीपीएस में)
(1)	(2)	(3)	(4 = 3-2)	(5)	(6)	(7 = 6-5)
सीपी (3 माह)	3.89	3.33	-56	71	44	-27
कॉर्पोरेट बॉण्ड						
एए (1 वर्ष)	4.00	3.86	-14	36	30	-6
एए (3 वर्ष)	4.90	4.64	-26	28	17	-11
एए (5 वर्ष)	5.60	5.59	-1	22	28	6
ए (3 वर्ष)	5.84	5.50	-34	122	103	-19
बीबीबी-माइन्स (3 वर्ष)	9.79	9.47	-32	517	500	-17
10-वर्ष जी-सेक	5.88	5.91	3	-	-	-

स्रोत: सीसीआईएल: एफ-ट्रैक:एफआईएमडीए; और ब्लूमबर्ग

सारणी 7: कॉर्पोरेट बॉण्ड स्प्रेड

रेटिंग	3-वर्ष कॉर्पोरेट बॉण्ड स्प्रेड				भिन्नता		
	कोविड-पूर्व			कोविड- पश्चात			
	31-दिसं-19	31-जन-20	28-फर-20	27-नव-20	5= (4-1)	6= (4-2)	7= (4-3)
	1	2	3	4			
							(आधार अंक)
एएए	59	60	90	17	-42	-43	-73
एए	103	104	128	69	-34	-35	-59
एए	136	140	167	103	-33	-37	-64
एए	175	178	207	150	-25	-28	-57
ए	315	278	307	300	-15	22	-7
ए	345	328	357	325	-20	-3	-32
ए	425	378	407	400	-25	22	-7
बीबीबी+	475	403	432	425	-50	22	-7
बीबीबी	500	428	457	450	-50	22	-7
बीबीबी	550	453	482	500	-50	47	18

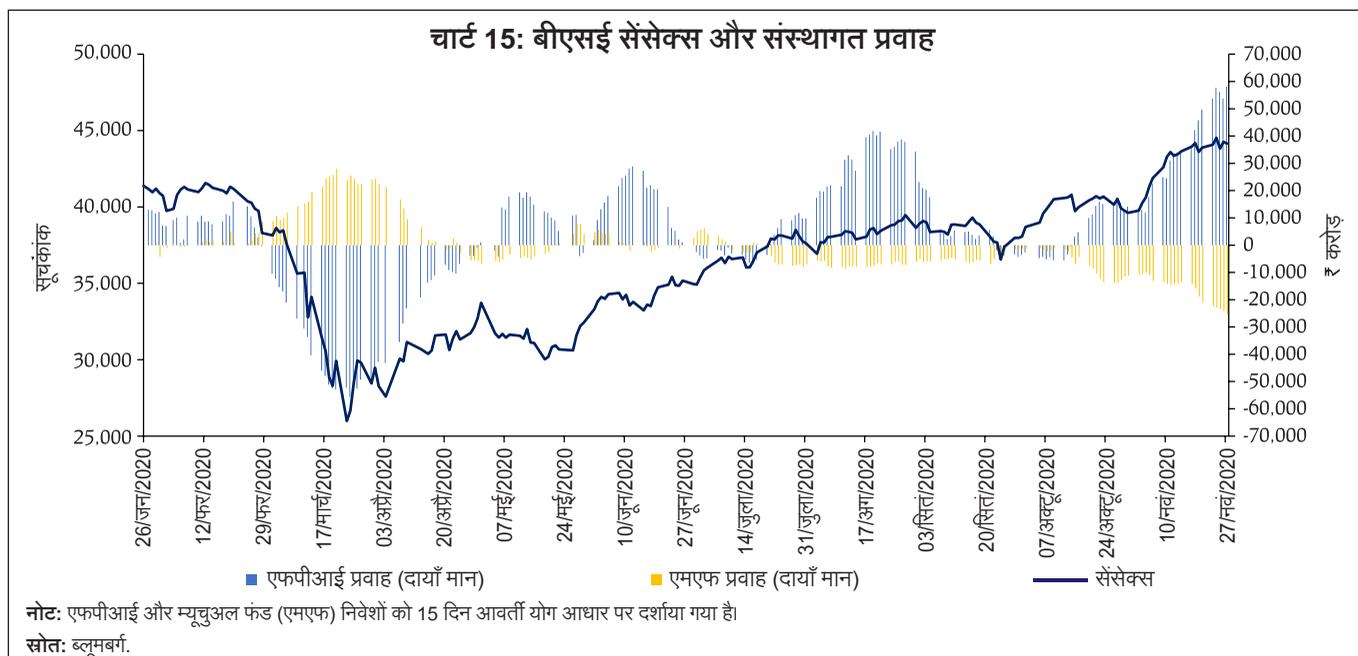
नोट: विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू एचओ) द्वारा 11 मार्च 2020 को कोविड-19 को महामारी घोषित किए जाने के बाद की अवधि को कोविड-पश्चात अवधि के रूप में माना जाता है।

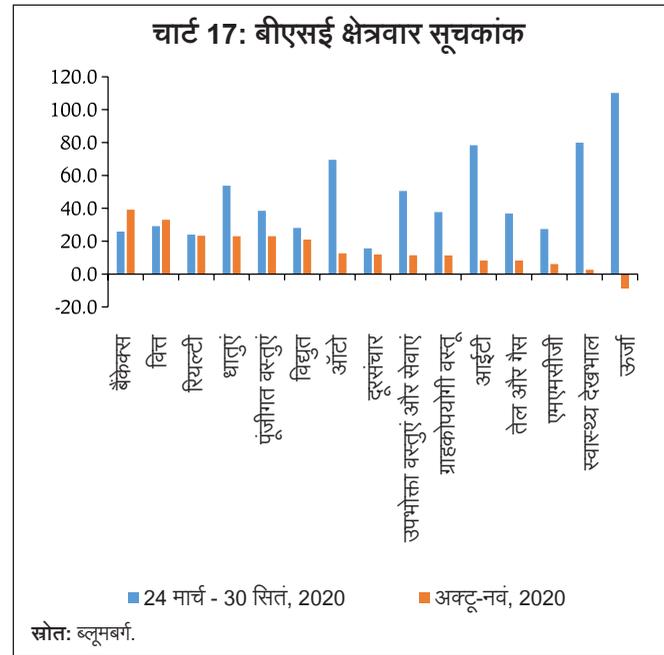
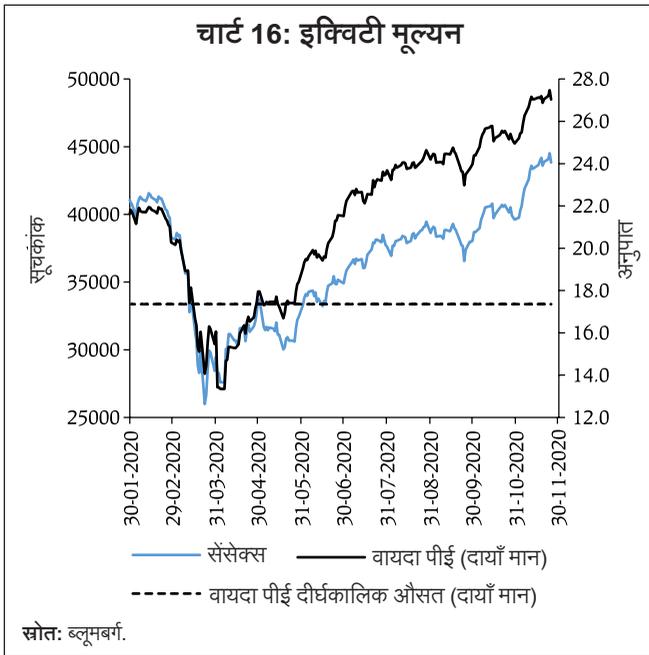
स्रोत: एफआईएमएमडीए

मार्च 2020 के बाद से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा और उधार दरों में नीतिगत रिपो दर में परिवर्तन के संचरण में सुधार आया है, जो अधिशेष चलनिधि, निभावकारी मौद्रिक नीति रुख, ऋणों के बाह्य बेंचमार्क-आधारित मूल्य निर्धारण, कमजोर पड़ी ऋण की मांग और नीतिगत दरों में कटौती के विलंबित असर के सम्मिलित प्रभाव का परिचायक है। माध्य सावधि जमा दर, जो मौजूदा कार्ड दरों को दर्शाती है, में मार्च से नवंबर 2020 के दौरान 143 आधार अंकों की भारी गिरावट

आयी है। इसी अवधि में 1-वर्ष माध्य एमसीएलआर में 90 बीपीएस की गिरावट आई है।

23 मार्च 2020 को बीएसई सेंसेक्स में 69.9 प्रतिशत की वृद्धि के साथ भारतीय इक्विटी बाजार में 25,981 के निचले स्तर से 27 नवंबर 2020 को 44,150 पर बंद हुआ। वैक्सिन से जुड़ी खबरों, अमेरिकी चुनावों के परिणाम और सरकार द्वारा घोषित प्रोत्साहन उपायों के कारण घरेलू इक्विटी बाजारों ने नई उंचाइयाँ



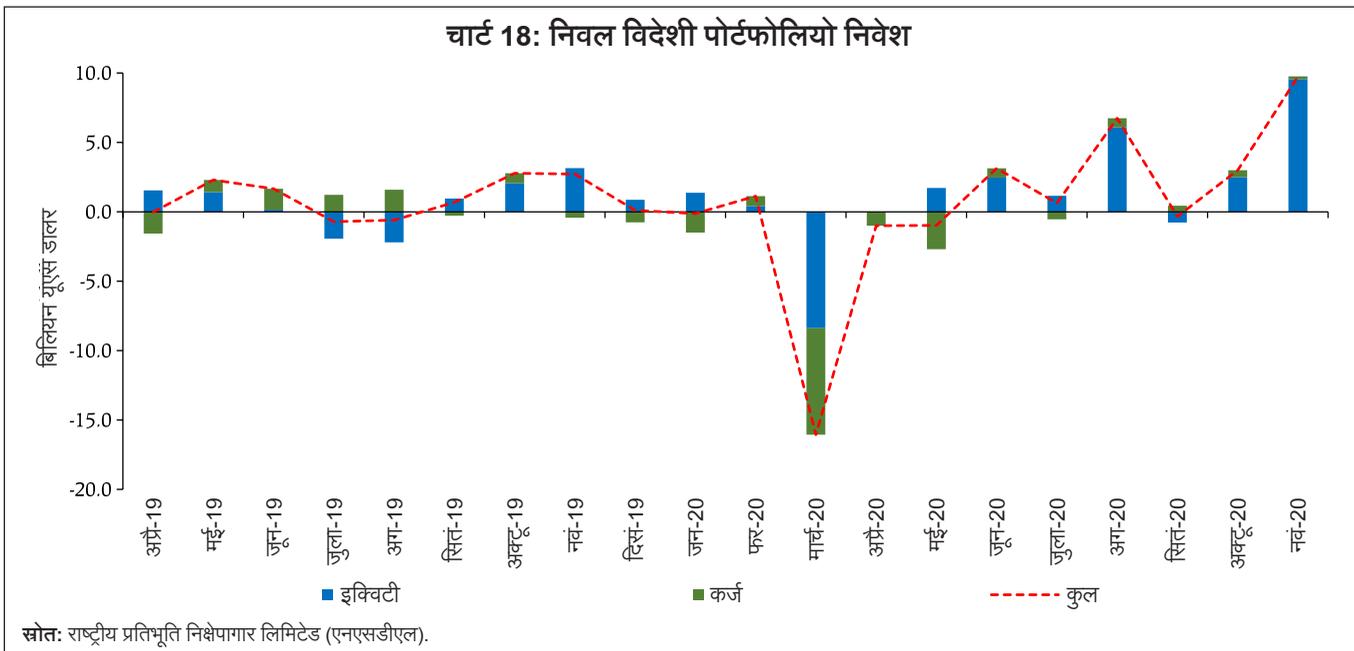


छुई (चार्ट 15)। इसने मूल्य-आय अनुपात (पीई) को नवंबर 2020 के अंत में इसके दीर्घकालिक औसत 17.4 से बढ़ाकर 27.2 कर दिया (चार्ट 16)।

इक्विटी बाजारों में आयी अचानक तेजी का कारण बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के शेयरों में आया उछाल भी था जिनकी आय में 2020-21 की दूसरी तिमाही में उम्मीद से बेहतर परिणाम आए थे और तेजी से वापसी की संभावनाएं भी बढ़ी थीं

(चार्ट 17)। नवंबर 2020 में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) की आमद सर्वकालिक उच्च स्तर पर थी, जिसका प्रमुख कारण था 9.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की इक्विटी खरीद जो कि पिछले महीने की गयी 2.5 बिलियन यूएस डालर से बहुत अधिक थी (चार्ट 18)।

विदेशी मुद्रा बाजार में, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये (INR) में अक्टूबर 2020 की तुलना में नवंबर 2020 के



दौरान 1.0 प्रतिशत की मामूली गिरावट आयी, हालांकि, यह मार्च 2020 के अंत में अपने प्रारंभिक स्तर से 2.2 प्रतिशत ऊपर रहा। 36-मुद्रा व्यापार-भारित प्रभावी विनिमय दर के दोनों सूचकांकों- नाममात्र और वास्तविक- की दृष्टि से आईएनआर में इसके एक महीने पहले के स्तर से नवंबर 2020 में 1.9 प्रतिशत की गिरावट आई।

पूँजी प्रवाह बहुत अच्छा रहने और साथ ही, व्यापार घाटे में पहले की तुलना में संकुचन आने से मार्च 2020 के अंत से आरक्षित निधि के भंडार में 97.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर अभिवृद्धि हुई है। नवंबर 2020 के अंत में, यह भंडार 574.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर था, जो 16.8 के आयात के समतुल्य था, या यूँ कहें कि यह जून 2020 के अंत में भारत के कुल मौजूदा बकाया बाह्य ऋण को पूरी तरह से कवर करने हेतु आवश्यक निधि से अधिक था (चार्ट 19)।

डिजिटल लेनदेन में निरंतर वृद्धि हुई और नवंबर 2020 के दौरान इसमें और अधिक गति आयी जिसमें थोक और खुदरा लेनदेन दोनों का योगदान रहा (तालिका 8)। खुदरा खंड में, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (NEFT) लेनदेन की मात्रा में नवंबर 2020 में 24.6 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गयी, जो एक महीने पहले दर्ज की गई वृद्धि (13.9 प्रतिशत) की तुलना में काफी अधिक है। नवंबर 2020 में एनईएफटी लेनदेन के मूल्य में

सारणी 8: 2020-21 में भुगतान लेनदेन

	(₹ करोड़ में)			
	आरटीजीएस	एनईएफटी	यूपीआई	आईएमपीएस
अप्रै.-20	64,43,653	13,06,406	1,51,141	1,21,141
मई-20	70,41,869	14,81,750	2,18,392	1,69,402
जून -20	86,51,978	19,06,586	2,61,835	2,06,951
जुला -20	83,35,279	19,63,113	2,90,538	2,25,775
अग-20	72,92,380	19,30,552	2,98,308	2,35,137
सितं-20	94,89,066	21,65,515	3,29,032	2,48,662
अक्टू-20	84,96,046	22,35,389	3,86,107	2,74,645
नवं-20	79,87,655	22,18,252	3,90,999	2,76,459

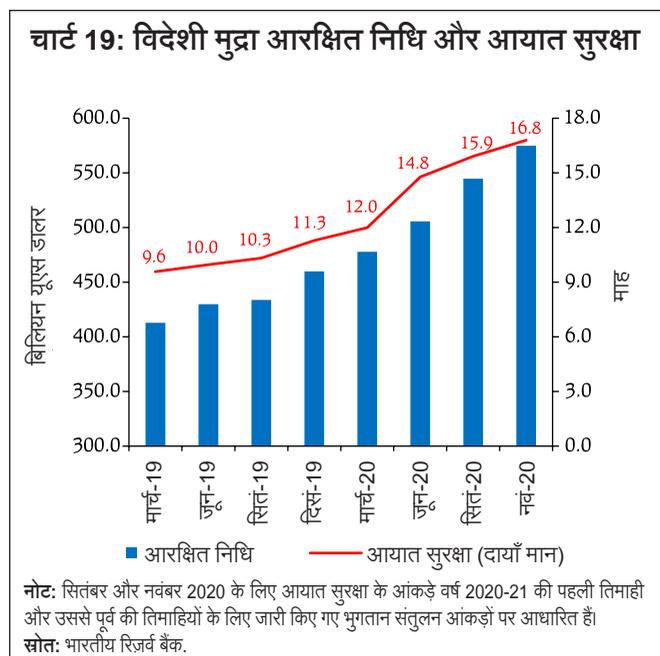
स्रोत: भारिबैंक

वृद्धि (27.9 प्रतिशत) अक्टूबर 2020 में दर्ज की गई वृद्धि (20.1 प्रतिशत) की तुलना में अधिक थी। नवंबर 2020 में एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) लेनदेन तेजी से बढ़ता हुआ लगभग 2.2 बिलियन हो गया, और इसमें मात्रा और मूल्य दोनों दृष्टियों से वृद्धि हुई। डिजिटल लेनदेन के अन्य प्रकारों में भी, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (NETC) में अत्यधिक तेजी का रुख देखा गया और तत्काल भुगतान सेवा (IMPS) में पिछले माह की तुलना में नवंबर 2020 में तीव्र वृद्धि देखी गई। थोक भुगतान खंड में, तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) लेनदेन में मात्रात्मक रूप से तेजी दर्ज की गयी।

V. निष्कर्ष

उच्च आवृत्ति संकेतकों में निहित उतार-चढ़ाव का सारांश यह है कि इस अंतर्निहित प्रवृत्ति से पता चलता है कि 2020-21 की दूसरी छमाही की शुरुआत ही आर्थिक गतिविधियों में जो तेजी आनी प्रारंभ हुई थी, वह बनी हुई है। इस भयानक महामारी की जिस दूसरी लहर के प्रकोप की आशंका थी, वह अभी भारत में नहीं देखी जा रही है, जिसके कारण समर्थनकारी समष्टि आर्थिक नीतियों वाले वातावरण में आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार बढ़ गयी है और अब अनलॉक की प्रक्रिया तेज होने से अर्थव्यवस्था अपनी सामान्य स्थिति में लौट रही है।

विभिन्न एजेंसियों द्वारा इस पूरे वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था में संकुचन के पूर्वानुमानों में कमी आनी पहले से ही शुरू हो चुकी है, और यदि बहाली की वर्तमान गति बनी रहती है, तो वर्ष की अंतिम तिमाही में अपेक्षित उछाल आधारभूत आकलन से भी अधिक होने की संभावना है। वर्तमान में नीतिगत जोर अर्थव्यवस्था के अधिक टिकाऊ वाहकों पर होने के कारण ड्राइवर्स की ओर बढ़



रहा है, निजी निवेश के लिए यह उपयुक्त अवसर है कि वह कैपेक्स के प्रति एहतियाती और डीलीवरेजिंग वाली धारणा को छोड़कर अपना ध्यान वर्तमान क्षमता के उपयोग और नई क्षमताओं के निर्माण की ओर लगाए। अनुभव और अनुभवजन्य साक्ष्य दोनों ने यह दिखाया है कि निवेश की वजह से आयी बहाली टिकाऊ होती है और इससे उपभोग व्यय और निर्यात दोनों में वृद्धि होती है। कृषि विपणन और श्रम-संहिताओं के क्षेत्र में हुए सुधारों से दक्षता और उत्पादकता लाभ में वृद्धि को सहारा मिलेगा।

वित्तपोषण की स्थिति अच्छी है। इस महामारी के दौरान, हाउसहोल्ड्स और निगमों की वित्तीय बचत में तेजी आई है, लेकिन इस बात का इंतजार है कि उन्हें उत्पादक निवेशों के रूप में रखा जाए न कि सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) और गैर-एसएलआर पेपर जैसे निष्क्रिय निवेशों के रूप में। आर्थिक गतिविधियों के पुनः पटरी पर आने के साथ ही, अब बैंक ऋणों में धीरे-धीरे तेजी आ रही है। आगे कंपनियों की कमाई बेहतर रहने के आसार हैं। विदेशी बचत की आपूर्ति बढ़ रही है, और भारत विदेशी निवेश को लेकर आशान्वित है। वर्ष 2020 के संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार की विजेता 'इन्वेस्ट इंडिया' रही है जो राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी है। इसके अलावा, ब्याज दरों की दृष्टि से देखें तो वित्तीय स्थितियां इतनी अनुकूल हैं

जितनी कई दशकों में नहीं थीं। महामारियों से भय का वातावरण बन जाता है और ऐसे में जोखिम विमुखता आ जाती है, लेकिन वे अपने साथ कई अवसर भी लेकर आती हैं और जिंदादिली दिखाने के नये द्वार खोलती हैं।

साथ ही, इस बात के दोगुने प्रयास करने की आवश्यकता है कि महँगाई- जो दूध में मक्खी के समान है- उसे निकाल फेंका जाए इससे पहले कि संवृद्धि की दिशा में बनते संवेग को यह मंद कर दे। अनियंत्रित रिटेलर मार्जिन पर लगाम और उपभोक्ताओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाए जाने की घटनाओं को कम करने सहित कुशल, प्रभावी और समयबद्ध आपूर्ति प्रबंधन से ही, बढ़ती महँगाई की कमर तोड़ी जा सकती है इससे पहले कि उसका प्रभाव और व्यापक हो जाए और वह राजकोषीय और मौद्रिक प्रोत्साहनों के इच्छित प्रभाव के विरुद्ध कार्य करने लगे। अच्छे समन्वय के साथ रसद अंतिम मील तक टीकों के देश-व्यापी भली-भांति और तेजी से वितरण के लिए बेहतर समन्वय के साथ आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं ताकि देश के आखिरी व्यक्ति तक उन्हें पहुंचाया जा सके। हालांकि, टिकाऊ बहाली के मार्ग में अभी भी कई बाधाएं हैं, तथापि यदि सभी हितधारकों द्वारा लगातार प्रयास किया जाएगा तो खोई हुई आय को फिर से हासिल किया जा सकेगा और/अथवा भारत को तीव्रतर संवृद्धि पथ पर अग्रसर करना संभव होगा।